मार्च, 2023, वर्ष : 44 अंक : 03
www.indiatibet.net

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

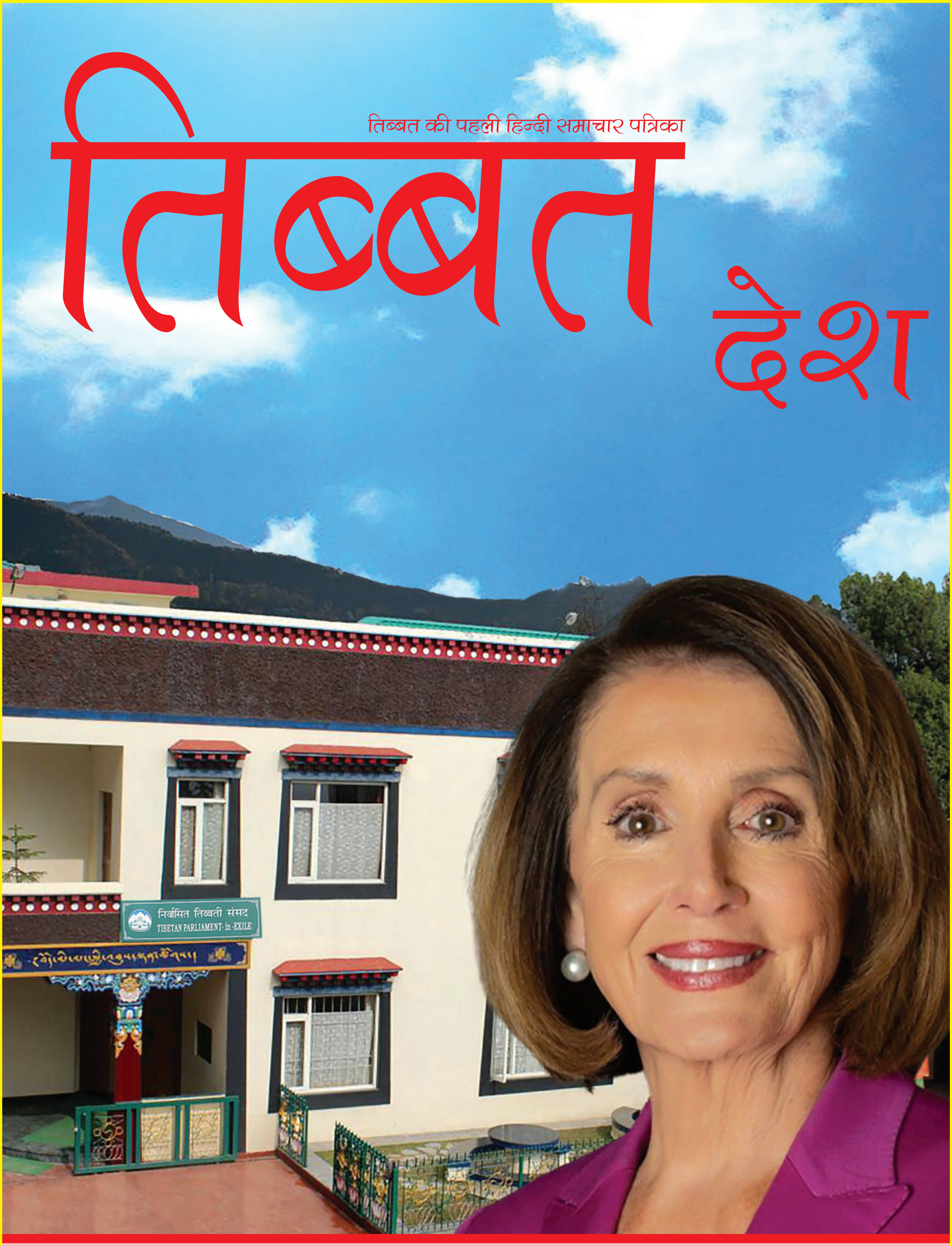

निर्वासित तिब्बती संसद ने अमेरिकी स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी के प्रति आभार प्रस्ताव पारित किया

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

तिब्बत देश

मार्च , 2023, वर्ष : 44 अंक : 03

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन, ताशी देकि

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग पेंपा छेरिंग।

समाचार -

• परम पावन दलाई लामा ने मलेशिया, स्वीडन और अमेरिका के मुस्लिम विद्वानों के साथ बातचीत की 1

• सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने परम पावन दलाई लामा के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की 2

• निर्वासिततिब्बती संसद ने अमेरिकी स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी के प्रति आभार प्रस्ताव पारित किया 3

• केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने १९८९ के शहीदों के सम्मान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया 4

• विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के ३० से अधिक सदस्य सीटीए द्वारा आयोजित ६४वीं तिब्बती जनक्रांति दिवस स्मरणोत्सव में शामिल हुए 5

• तिब्बती लेखक को चार साल जेल की सजा की पुष्टि जांगकर जामयांग ने स्कूलों में तिब्बती शिक्षा बंद करने के चीन के कदम की आलोचना की थी 6

• संयुक्त प्रेस मीट में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत में जारी दमन पर चिंता जताई 7

• चेक विदेश मंत्री लिपावस्की ने भारत यात्रा के दौरान चीन-तिब्बत संघर्ष और आपसी व्यापार पर चर्चा की 8

• तिब्बतियों ने पूरी दुनिया में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ मनाई 9

• भारत में तिब्बत समर्थक समूहों ने ६४वां तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस मनाया 10

समाचार -

• तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए असम में जन आंदोलन पर 'फ्री तिब्बत! वॉयस फ्रॉम असम' पुस्तक का विमोचन 11

• ताइवान में सैकड़ों तिब्बत समर्थकों ने तिब्बत के लिए शांति रैली निकाली 12

• चीन के साथ संबंधों पर यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की नजर तिब्बत के ताजा घटनाक्रम पर 13

• संयुक्त राष्ट्र निकाय ने तिब्बत में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन को माना और चीन को सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा 14

• ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चस्तरीय खंड में 'तिब्बत में स्वतंत्रता' पर चिंता व्यक्त की 15

• तिब्बत के लिए नवगठित इतालवी संसदीय इंटरग्रुप का इतालवी सीनेट भवन में शुभारंभ 16

• तिब्बत हाउस ब्रासिल और यूआरआईआई ने संयुक्त रूप से शांति के लिए विज्ञान और धर्म के उपयोग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की 17

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

❖ तिब्बती जनक्रांति दिवस पर साम्राज्यवादी चीन की विश्वयापी आलोचना

तिब्बती जनक्रांति दिवस की 64वीं वर्षगाँठ 10 मार्च, 2023 को भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशो में उत्साहपूर्वक मनाई गई। तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों का यह विश्वयापी उत्साह प्रशसनीय है। उपनिवेशवादी चीन सरकार विभिन्न देशो को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देती रहती है इसके बावजूद तिब्बती आंदोलन का सहयोग एवं समर्थन विश्व स्तर पर बढ़ता जा रहा है। निर्वासित तिब्बत सरकार, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धरमशाला से संचालित है, इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें तिब्बती सांसद भी सम्मिलित थे। वास्तव में यह सरकार विश्व के अनेक देशो में रह रहे तिब्बतियों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान से गठित अर्थात् निर्वासित सरकार है। इसका निर्वाचन लोकतांत्रिक पद्धति से कराया जाता है। परम पावन दलाई लामा अपने समस्त राजनीतिक अधिकार निर्वासित तिब्बत सरकार को सौंप चुके हैं। वे स्वयं राजप्रमुख या शासनप्रमुख नहीं हैं। इसी से स्पष्ट है कि निर्वासित तिब्बत सरकार द्वारा तिब्बती जनक्रांति दिवस के अवसर पर जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, वह तिब्बती जनभावना का प्रतीक है। यह तिब्बत समर्थकों की भावना की भी निशानी है। उम्मीद की जानी चाहिये कि चीन सरकार इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

तिब्बत जनक्रांति दिवस के अवसर पर कई देशो की संसद में तिब्बत की चिंताजनक आंतरिक स्थिति पर खुलकर चर्चा की गई। वहाँ के जनप्रतिनिधि चीनी दबाव की उपेक्षा करते हुए तिब्बत के पक्ष में खड़े हैं। उनके लिये तिब्बत समस्या एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कर चीन ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उसने लोकतांत्रिक आदर्शो एवं मानवीय मूल्यों का उल्लंघन किया है। स्वतंत्र देश पर साम्राज्यवादी चीन का आधिपत्य पूर्णतः अस्वीकार्य है। भारतीय संसद में भी समय-समय पर तिब्बत की चर्चा हुई है। ऐसी चर्चा होती रहे तो ठीक रहेगा। तथाकथित भारत-चीन संबंध के नाम पर ऐसी चर्चा से दूर रहना नुकसानदेह है। चीन ने ''पंचशील'' और ''हिन्दी चीनी भाई-भाई'' के संकल्प को भी महत्वहीन समझा। भारत के शांति प्रयासों के विपरीत वह युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने 1962 में बहुत बड़े भारतीय भूभाग पर अपना गैरकानूनी कब्जा कर लिया। वह अब भी भारत के अटूट अंग अरुणाचल प्रदेश में कई नामों का चीनीकरण कर रहा है। चीन 1962 के बाद भी भारत को चारों ओर से घेरने, इसे अपमानित करने तथा नये-नये भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे स्थापित करने की विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। सराहनीय बदलाव यह है कि अब भारत सरकार चीन को उसी की भाषा में मुँहतोड़ जवाब दे रही है। अपने व्यापक राष्ट्रीय हित, अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति तथा कूटनीतिक रणनीति के अनुरूप भारत सरकार को चाहिये कि वह भारतीय संसद में उद्बोधन के लिये दलाई लामा को आमंत्रित करे। भारत की प्राचीन संस्कृति की समृद्धि में उनके सराहनीय योगदान के लिये उन्हें ''भारत रत्न'' से सम्मानित किया जाये।

तिब्बत की निर्वासित संसद में लगातार कई वर्षो से तिब्बती संघर्ष में सक्रिय साथ देने के लिये अमरीकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैंसी पैलोसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन अभिनंदन योग्य है। तिब्बत के अन्य कार्यालयों द्वारा भी कृतज्ञता ज्ञापन का यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नैंसी पैलोसी के प्रयासों के परिणामस्वरूप अमरीकी सरकार तिब्बत के विषय में चीन सरकार के विरूद्ध खड़ी है। तिब्बत में मानवाधिकरों का हनन लगातार जारी है। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को चीन सरकार बर्बाद कर रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है कि वह चीनी धमकियों की परवाह किये बिना तिब्बत के पक्ष में बोले। अपने राष्ट्रीय हित तथा अपनी संप्रभुता को चीन के समक्ष समर्पित नहीं किया जा सकता। तिब्बती संसद ने मार्च के अपने बजट सत्र में तिब्बत की दयनीय स्थिति पर विशेष चर्चा करते हुए तिब्बतियों के प्रति अपनी एकजुटता का संकल्प व्यक्त किया है। चीन के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता में भारत आवष्यक रूप से तिब्बत की दयनीय स्थिति को उठाये।

विश्व के अनेक देशो में स्थित चीनी दूतावासों पर विरोध प्रदर्शन कर तिब्बती जनक्रांति दिवस की वर्षगाँठ मनाई गई। तिब्बत के विषय में प्रत्येक देश में जागरुकता बढ़ती जा रही है। इसी मार्च माह में तिब्बत सरकार में सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के कालोन अर्थात् मंत्री नोर्गिन डोल्मा तथा इसके महासचिव माननीय कर्मा जी ने अपने ताइवान प्रवास में तिब्बत की स्थिति के बारे में वहाँ के लोगों को जागरुक किया है। उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री, संसद के स्पीकर, सांसदों, मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष समर्थक संगठनों, गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों से वार्ता की है। उन्होंने अपील की है कि वे तिब्बत समस्या का समाधान करने के लिये चीन पर दबाव बढ़ायें।

चीन सरकार को ताइवान में तिब्बत की चर्चा बिल्कुल बर्दाष्त नहीं है। इसके बावजूद ताइवान में नोर्गिन डोल्मा और कर्मा की प्रत्येक वार्ता सार्थक रही। ताइवान ने चीनी अत्याचार के विरूद्ध तिब्बती संघर्ष में खुलकर सहयोग एवं समर्थन देते रहने का आश्वासन दिया है। चीनी दमनकारी नीति, जो तिब्बत में 1959 से लगातार जारी है, के खिलाफ सभी देशो में अधिकाधिक विरोध प्रदर्शन होना चाहिये। विश्वभर से चीन को संदेश जाना चाहिये कि उसकी क्रूर विस्तारवादी आमानवीय नीति का जोरदार विरोध और भी अधिक सुसंगठित तथा तीव्र किया जायेगा। तिब्बती जनक्रांति दिवस का वास्तविक संदेश यही है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)
मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ परम पावन दलाई लामा ने मलेशिया, स्वीडन और अमेरिका के मुस्लिम विद्वानों के साथ बातचीत की

tibet.net, २०मार्च, २०२३

धर्मशाला। आज २०मार्च की सुबह मलेशिया, स्वीडन और अमेरिका के मुस्लिम विद्वानों के एक समूह ने धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा के निवास पर उनसे मुलाकात की।

परम पावन ने विद्वानों के साथ बातचीत में शांतिपूर्ण और करुणाशील विश्व के लिए अपनी चार प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक- धार्मिक सद्भाव- को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

परम पावन दलाई लामा ने कहा, 'सभी धर्मों के अलग-अलग दर्शन हो सकते हैं लेकिन सभी धर्म करुणा और अहिंसा (शांति) के प्रचार को लेकर एकमत हैं।' आगे बोलते हुए परम पावन ने धर्म के नाम पर संघर्ष की निरर्थकता की ओर इशारा किया और कहा कि धर्म में विश्वास की स्वीकृति या अस्वीकृति हर व्यक्ति की निजी पसंद है।

परम पावन ने कहा, 'धर्म मानव निर्मित है लेकिन सभी धर्मों का सार और संदेश एक ही है। इसलिए धर्म के नाम पर विवाद पैदा करने का कोई कारण नहीं है।'

उन्होंने आगे तिब्बती साम्राज्य में मुसलमानों और तिब्बतियों के बीच के विशेष संबंधों के बारे में याद दिलाया जब दोनों प्रमुख व्यापारिक भागीदार थे। परम पावन ने बताया कि दोनों समुदायों के बीच मित्रता आज भी बरकरार है। परम पावन ने अंत में कहा कि तिब्बती सरकार भी मुस्लिम समुदाय को सम्मान के साथ देखती है। इसके साथ ही उन्होंने आज मुस्लिम विद्वानों से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने परम पावन दलाई लामा के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की

tibet.net, ०६ मार्च, २०२३

धर्मशाला। सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने आज ०६मार्च की प्रातः परम पावन दलाई लामा के साथ सुगलगखांग में परम पावन के निवास पर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। सिक्योंग ने परम पावन को इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका के अपने हाल के आधिकारिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सिक्योंग ने पिछले साल दिसंबर में परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी अंतिम मुलाकात के बाद से १६वें कशाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियों की जानकारी उन्हें दी।

सिक्योंग ने परम पावन को अपनी पहली यात्रा के तौर पर ३०-३१जनवरी को इंग्लैंड की यात्रा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने मीडिया, थिंक टैंक, छात्रों और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ-साथ तिब्बत में रह रहे और तिब्बत के बाहर रह रहे तिब्बतियों बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए कई बार गंभीर और लंबी बातचीत की। इंग्लैंड दौरे के बाद सिक्योंग ने वाशिंगटन डीसी में सांसदों के साथ शृंखलाबद्ध बैठकों में भाग लिया और विशेष रूप से तिब्बत विधेयक को लागू कराने में उनका समर्थन मांगा। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में तिब्बत के कई प्रमुख समर्थकों और मित्रों के साथ बातचीत की। डीसी में उनकी लगातार आधिकारिक कार्यक्रमों के बीच ही अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में तिब्बत बिल को फिर से पेश किया गया।

तिब्बत विधेयक को फिर से पेश किए जाने के बाद सिक्योंग ने ०८फरवरी को कैपिटोल बिल्डिंग में स्पीकर एमेरिटस नैन्सी पेलोसी और कांग्रेसी जिम मैकगवर्न से मुलाकात की। उन्होंने लंबे समय से तिब्बत समर्थक कांग्रेस सदस्य क्रिस्टोफर एच. स्मिथ से भी मुलाकात की जो चीन पर कांग्रेस-कार्यकारी आयोग (सीईसीसी) के अध्यक्ष हैं। उन बैठकों के दौरान सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर की स्थिति, परम पावन दलाई लामा और सीटीए की तिब्बत मुद्दे को हल करने की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डीसी में सांसदों और सरकारी अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सिक्योंग ने पीआरएम और यूएसएआईडी के प्रमुखों से भी मुलाकात की। पीआरएम और यूएसएआईडी निर्वासन में राजनीतिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीटीए के धन प्राप्त करने के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। भविष्य की रणनीति बनाने के लिए सिक्योंग की दोनों संस्थाओं के साथ गहन चर्चा हुई।

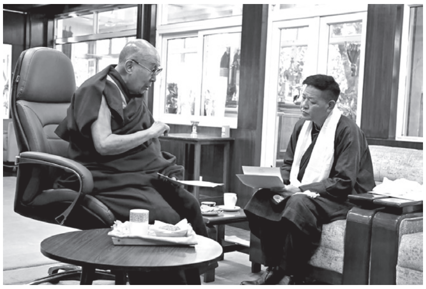

वाशिंगटन डीसी में अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अमेरिका में कोलोराडो, यूटा, पोर्टलैंड और सिएटल में तिब्बती समुदायों और कनाडा में वैंकूवर, विक्टोरिया द्वीप और अल्बर्टा का दौरा किया। जनता के साथ बातचीत के दौरान सिक्योंग ने द्विदलीय और द्विसदनीय तिब्बत विधेयक को अधिनियमित करने में संबंधित सांसदों के दृढ़ प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने १६वें कशाग के उपक्रमों और आने वाले वर्षों के लिए इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तिब्बती बस्तियों के निर्वाह और सीटीए कर्मचारियों के सशक्तिकरण की योजनाएं शामिल हैं।

◆ निर्वासिततिब्बती संसद ने अमेरिकी स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी के प्रति आभार प्रस्ताव पारित किया

tibet.net, १८मार्च, २०२३

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद ने बजट सत्र के चौथे दिन आज १८मार्च की सुबह सर्वसम्मति से परम पावन दलाई लामा और तिब्बत के सबसे पुराने और निरंतर मित्रों में से एक होने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित किया।

सांसद छेरिंग ल्हामो ने निर्वासित तिब्बती संसद में पेश प्रस्ताव में अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए द्विदलीय प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत करने के लिए अध्यक्ष एमेरिटा पेलोसी के अभूतपूर्व योगदान और समर्थन को रेखांकित किया। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तिब्बत के प्रति बार-बार जताई गई अटूट प्रतिबद्धता दुनिया भर में, विशेष रूप से तिब्बत के अंदर के तिब्बती लोगों में आशा और प्रेरणा का संचार करता है और इसका एक बड़ा स्रोत साबित हुआ है। तिब्बती सांसदों ने चीन द्वारा उत्पीड़ित लोगों की स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा में स्पीकर पेलोसी के निडर नेतृत्व, प्रतिबद्धता और अडिग दृढ़ता की भी सराहना की। स्पीकर पेलोसी ने अपनी अडिग दृढ़ता को बीजिंग द्वारा बार-बार चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद पिछले साल अगस्त में ताइवान की अपनी यात्रा के दौरान उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया था। संसदीय सत्र में आज पेश किए गए प्रस्ताव को सभी सांसदों का सर्वसम्मत समर्थन मिला। इसके अलावा निर्वासित तिब्बती संसद ने सर्वसम्मति से स्पीकर पेलोसी को सम्मानित करने के लिए निकट भविष्य में कृतज्ञता ज्ञापन समारोह का भव्य तरीके से आयोजन करने का संकल्प व्यक्त किया। स्पीकर पेलोसी यकीनन तिब्बत के संकल्पित और प्रभावशाली समर्थकों में से एक रही हैं और अब भी हैं।

दो ऐतिहासिक दशकों से अधिक समय तक अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन- प्रतिनिधि सभा- का नेतृत्व करने के बाद पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नवंबर २०२२में पद से इस्तीफा दे दिया था।

◆ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने १९८९ के शहीदों के सम्मान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया

tibet.net, ०८ मार्च, २०२३

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के धर्म और संस्कृति विभाग ने चीनी सरकार के खिलाफ १९८९ के विरोध- प्रदर्शन में भाग लेने वाले शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए एक घंटे की प्रार्थना सभा का आयोजन किया।

प्रार्थना सभा का आयोजन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायिक आयुक्त कर्मा दादुल, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, न्यायिक आयुक्तों, कलोंन और सीटीए के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया।

०८ मार्च १९८९ को चीनी सरकार ने हजारों शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इन प्रदर्शनकारियों में भिक्षु, भिक्षुणियां और आम लोग शामिल थेजो चीनी अधिकारियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। इस दिन को तिब्बत के राजनीतिक इतिहास में सबसे दुखद क्षण माना जाता है क्योंकि सरकारी दमन में अनेक तिब्बती मारे गए थे। मार्शल लॉ के दमन में अनेक प्रदर्शनकारी अपंग हुए और कई कैद कर लिए गए थे।

तब से हर साल सीटीए ०८ मार्च को प्रार्थना सभा का आयोजन करता है ताकि उन तिब्बती हमवतनों को याद किया जा सके और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके,जिन्होंने तिब्बत के लिए अपने जीवन और अंगों को बलिदान कर दिया।

प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने कहा, 'इस वार्षिक प्रार्थना सभा के माध्यम सेहम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बलिदानों को याद करते हैं और हम उनके साथ अपनी हार्दिक एकजुटता व्यक्त करते हैं। जब हम इस घटना का स्मरण करते हैं तो साथ ही में हम यह भी याद करते हैं कि तिब्बत अब भी गंभीर स्थिति में है और तिब्बतियों को शृंखलाबद्ध दमनकारी उपायों से दबाया जा रहा है।'सिक्योंग ने लंबे समय से चले आ रहे चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए अपने प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

सिक्योंग ने हाल ही में परम पावन के साथ अपनी व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान परम पावन दलाई लामा द्वारा की गई शुभ भविष्यवाणी का भी उल्लेख किया। परम पावन की वह शुभ भविष्यवाणी इस वर्ष तिब्बत और चीन की यात्रा करने की उनकी चिरस्थायी इच्छा के लिए अनुकूल और आशापूर्ण होने का संकेत देती है। इसी तरह, परम पावन ने इस वर्ष तिब्बत की यात्रा करने की गहरी इच्छा व्यक्त की है।

सिक्योंग ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा,'हमें आशावान और आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारा संघर्ष सफल होगा।'

◆ विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के ३० से अधिक सदस्य सीटीए द्वारा आयोजित ६४वीं तिब्बती जनक्रांति दिवस स्मरणोत्सव में शामिल हुए

tibet.net , १० मार्च, २०२३

धर्मशाला। आज १० मार्च को यहां धर्मशाला में आयोजित ६४वीं तिब्बती जनक्रांति दिवस के स्मरणोत्सव में विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के ३० से अधिक सदस्य शामिल हुए।

इस अवसर पर मेक्सिको, यूरोपीय संसद, लिथुआनिया और ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने तिब्बती नेतृत्व और निर्वासित तिब्बतियों के साथ एकजुटता जताते हुए उन तिब्बती शहीदों को सम्मानित करके इस दिन को याद किया, जो चीनी सरकार के कब्जे के खिलाफ निडरता से खड़े रहते हुए बलिवेदी पर चढ़ गए थे।

स्मरणोत्सव कार्यक्रम में यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल में सांसद मिकुलस पेक्सा, सांसद सलीमा येनबो, सांसद हेंस हेइड और सांसद ऑसरा मालदेइकिएन शामिल थे। इनके सहयोग के लिए वहां से संसदीय सहायक सैमुअल वी सैमुअल वैंको, टॉमस एडमेक, मार्टिना टेसेरी, एडुआर्ड एलेक्स सार्री भी थे। इसी तरह मैक्सिको संसद के प्रतिनिधिमंडल में सांसद लिडिया गार्सिया अनाया, सांसद दुलस मारिया कोरिना, सांसद इनेस पारा ज़ुआरेज़, सांसद सल्वाडोर कारो कैबरेरा, सांसद मारिया एलेना लिमोन गार्सिया, सांसद मा टेरेसा रोसौरा ओचोआ मेजिया, सांसद जूलियट मेजिया इबनेज़,सांसद लिडिया पेरेज़ बारसेनास, सांसद जोस मिगुएल डे ला क्रूज़ लीमा और लिथुआनियाई सांसद अरुणास वालिंस्कास शामिल थे।

इस समारोह में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तीनों लोकतांत्रिक स्तंभों के प्रमुख, कालोन, सांसद, सचिव, सीटीए के अधिकारी, निदेशक और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

समारोह में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल और सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने क्रमश संसद और कशाग की ओर से बयान पढ़े।

मुख्य अतिथि सांसद मिकुलस पेक्सा ने अपने मुख्य भाषण में तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए परीक्षण जैसी चीनी दमनकारी नीतियों की यूरोपीय संघ की ओर से कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चीन की यह दमनकारी नीतियां तिब्बतियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और अनिवार्य औपनिवेशिक बोर्डिंग प्रणाली के स्कूलों माध्यम से तिब्बती बच्चों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में जबरन आत्मसात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन दबाव वाले मुद्दों पर यूरोपीय संघ द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सांसद पेक्सा ने कहा,'मुझे विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूं उससे हमारे सभी साथी सांसद सहमत होंगे।'उन्होंने कहा कि हम तिब्बती लोगों पर हुए अन्याय को उजागर करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए हरसंभव प्रयास करेंगे। हम चीन को इस अपराध के लिए जवाबदेह ठहराना जारी रखेंगे।

विशेष अतिथि और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (एनईडी) के अध्यक्ष डेमन विल्सन ने स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र के लिए तिब्बती लोगों के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तिब्बती लोगों के प्रेरक अदम्य साहस और अविचलित भावना की सराहना की।

उन्होंने तीन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए बताया कि विश्व किस प्रकार तिब्बत और तिब्बती लोगों से प्रेरणा ले सकता है। पहला,निर्वासन में तिब्बती लोगों द्वारा सत्य और न्याय की खोज में अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों से डगमगाए बिना ६४ वर्षों तक संघर्ष को जारी रखना दुनिया भर के सभी स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों के लिए प्रेरणा का एक मॉडल बन सकता है। दूसरे बिंदु के तौर पर उन्होंने लोकतंत्र की संपन्न तिब्बती प्रणाली स्थापित किए जाने को दुनिया भर में नैतिक उदाहरण के रूप में की प्रशंसा की। तीसरे में उन्होंने तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा के सौभाग्य और आशीर्वाद की याद दिलाई, जिन्हें विश्व स्तर पर प्यार किया जाता है और परेशान दुनिया में आशा की किरण के तौर पर उम्मीद के साथ देखा जाता है।

उन्होंने कहा,'दुनिया को तिब्बत की जरूरत है और तिब्बतियों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। जानिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। न्याय, लोकतंत्र और अहिंसा के सिद्धांतों में दृढ़ रहने के लिए हमेशा गतिशील बने रहना जारी रखें। आजादी के लिए आपका संघर्ष दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए आशा की किरण है।'

विशेष अतिथि के रूप में लिथुआनिया के सांसद अरुणस वैलिंस्कास ने सोवियत संघ के कब्जे के तहत बड़े होने के अपने अनुभवों और उन अशांत समय के दौरान लिथुआनिया के लोगों द्वारा सीखे गए सामूहिक सबक से सबको अवगत कराया। उन्होंने लिथुआनिया के स्वतंत्रता संघर्ष में परम पावन दलाई लामा द्वारा दिखाए गए करुणा और ईमानदारी का पालन करने में उनकी दृढ़ता और लचीलेपन को महत्वपूर्ण तत्व बताया।

उन्होंने कहा,'हम परम पावन द्वारा लिथुआनिया के प्रति दिखाई गई करुणा और समर्थन को कभी नहीं भूलेंगे और हम आशा करते हैं कि हम उस ऋण का एक हिस्सा चुका सकते हैं।'इसके साथ ही उन्होंने तिब्बत के जल्द ही स्वतंत्र होने और इसका आनंद लेने के प्रति अपने दृढ निश्चिय मत को व्यक्त किया।

उन्होंने अंत में कहा,'जान लें कि आपके प्रयासों का पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में दोस्तों द्वारा बारीकी से पालन किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। मानवाधिकारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध रहें।'

विशिष्ट अतिथि सल्वाडोर कारो कैबरेरा ने दुर्दांत उत्पीड़क चीन के खिलाफ तिब्बती लोगों की नरमी और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने तिब्बती

लोगों को स्वतंत्रता, न्याय और अहिंसा की अपनी खोज को मजबूती से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

धर्मशाला में किसी उच्चस्तरीय विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा न केवल तिब्बतियों के साथ उनकी गहरी एकजुटता और उनके स्थायी समर्थन को व्यक्त करता है बल्कि चीन को तिब्बती लोगों के प्रति किए अन्याय की जवाबदेही लेने के लिए भी साहसिक और प्रेरणादायी संदेश भेजता है और चीन से वैश्विक समुदाय के सदस्य के नाते जिम्मेदार बनने के लिए कहता है।

तिब्बती लेखक को चार साल जेल की सजा की पुष्टि

◆ जांगकर जामयांग ने स्कूलों में तिब्बती शिक्षा बंद करने के चीन के कदम की आलोचना की थी

rfa.org,लोब सॉकत्सांग, १३ मार्च, २०२३

लगभग तीन साल पहले चीनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक तिब्बती लेखक को 'अलगाववाद भड़काने और इंटरनेट चैट समूहों में अफवाहें फैलाने'के आरोप में चार साल की जेल की सजा दी गई है। स्थिति की जानकारी रखने वाले तिब्बतियों ने इसकी पुष्टि की है।

अब ४५ वर्ष के हो चुके ज़ंगकर जामयांग ०४ जून, २०२० की रात को अचानक गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन्हें दक्षिण-पश्चिमी चीनी प्रांत सिचुआन में तिब्बती क्षेत्रन्गाबा के क्यूंगचू काउंटी में अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया था।

क्षेत्र के अंदर के एक तिब्बती ने बताया कि बहुत समय तकउनके परिवार को उनके ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी कोई सूचना परिवार को नहीं थी।

सूत्र ने 'रेडियो फ्री एशिया'को बताया, आखिरकार परिवार को पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर 'अलगाववाद भड़काने'और विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेने का आरोप लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि उन्हें सिचुआन प्रांत में चेंगदू शहर के पास मेनयांग जेल में हिरासत में रखा गया है और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है।

चीनी अधिकारी तिब्बती राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले तिब्बती लेखकों और कलाकारों को अक्सर हिरासत में लेते हैं, जिनमें से कई को जेल की लंबी सजा सुनाई जाती है।

कई बार, तिब्बतियों ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करके अपनी भाषा और संस्कृति को दबाने के चीनी प्रयासों का विरोध किया है, जिन्हें आम तौर पर बल प्रयोग के द्वारा दबा दिया जाता है।

जमयांग तिब्बती और चीनी दोनों भाषाएं धाराप्रवाह बोल सकते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है और 'डांग चार'सहित तिब्बती साहित्यिक पत्रिकाओं में वह लिखते रहे हैं।

मार्च- २०२० के आसपास जमयांग ने स्कूलों में तिब्बती भाषा पढ़ाने के महत्व के बारे में बोलना शुरू किया था। जब अधिकारियों ने स्कूलों में क्षेत्र की मातृभाषा के शिक्षण को बंद करने के लिए नीतियों को लागू करना शुरू किया तो उन्होंने चीनी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया था।

जमयांग विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने तिब्बतियों को प्रोत्साहित किया कि वे तिब्बतियों को अपनी भाषा का उपयोग करने और पढ़ाने से रोकने के चीनी सरकार के प्रयासों की निंदा करें।

स्थिति की जानकारी रखने वाले एक अन्य तिब्बती ने कहा कि अधिकारियों ने लेखक से कई बार पूछताछ की और उसके लैपटॉप,कंप्यूटर और मोबाइल फोन की तलाशी ली। उन्होंने उन्हें कई बार हिरासत में भी लिया।

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु परम पावन का जिक्र करते हुए सूत्र ने कहा, 'जमयांग सक्रिय रूप से परम पावन दलाई लामा की महानता और तिब्बती भाषा के संरक्षण के बारे में ऑनलाइन चैट समूहों में जानकारी पोस्ट कर रहे थे।'

जमयांग ने १९९८ में तिब्बत छोड़ दिया और भारत में दलाई लामा का निवास और निर्वासन में तिब्बती सरकार के मुख्यालय धर्मशाला में रहते हुए अंग्रेजी सीखी।

लेकिन २००२ में वह तिब्बत लौट आए और संयुक्त राष्ट्र संगठनों और संयुक्त राज्य अमेरिका के गैर सरकारी संगठनों के लिए दुभाषिया का काम करने लगे। उन्होंने क्षेत्र में आनेवाले पर्यटकों के लिए टूर गाइड और अनुवादक के रूप में भी काम किया।

२०१९ में अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन वह कोविड-१९ महामारी के बीच यात्रा नहीं कर सके।

दूसरे सूत्र ने कहा कि ०४ जून, २०२० को वह अचानक गायब हो गए और बहुत समय के बाद ही उसके परिवार को चीनी पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

◆ संयुक्त प्रेस मीट में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत में जारी दमन पर चिंता जताई

tibet.net, १० मार्च, २०२३

धर्मशाला। तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने की दिशा में अपनी वास्तविक एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित करने और तिब्बत के अंदर चीन की दमनकारी नीतियों पर चिंता व्यक्त करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के विशिष्ट अतिथियों ने तिब्बती प्रशासन द्वारा आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बात की। इस प्रेस मीट का आयोजन सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा आज १० मार्च की दोपहर तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाई गई थी।

इस प्रेस मीट में आने वाले मेहमानों में माननीय मिकुलस पेक्सा के नेतृत्व में चार सदस्यीय यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल,माननीय सल्वाडोर कारो कैबरेरा (तिब्बत समर्थक समूह के सदस्य) के नेतृत्व में मेक्सिको का नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल और लिथुआनियाई संसद के सदस्य माननीय अरुणस वालिंस्कास शामिल थे।

सिक्योंग ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस मीट को संबोधित करते हुए यूरोपीय संसद के सदस्य माननीय मिकुलस पेक्सा ने सीटीए और धर्मशाला स्थित अन्य तिब्बती संस्थानों में अपने और अपने साथी सांसदों

के सामूहिक अनुभवों की जानकारी दी और कहा कि उन्होंने तिब्बती प्रशासन केंद्र के भीतर बहुत अच्छा सहयोग देखा और यहां निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के साथ अन्य देशों में बसे तिब्बतियों को प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट देखभाल सेवाएं देखी हैं। उन्होंने कहा, 'हमने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसके मेजबान देश भारत के बीच सहयोग के बहुत अच्छे संकेत भी देखे हैं।'

मैक्सिको के नौ सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाले माननीय सल्वाडोर कारो कैबरेरा ने आज १० मार्च की प्रातः परम पावन दलाई लामा के साथ बैठक में मिली अपनी संतुष्टि के बारे में बात की। उन्होंने तर्क दिया कि परम पावन तिब्बत के मुद्दे के लिए उचित और वैध (समाधान) हैं। तिब्बत मुद्दे के समर्थन के एक संकेत के रूप में अपनी धर्मशाला यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 'वन चाइना पॉलिसी (एक चीन नीति)की जोरदार निंदा की जो तिब्बती पहचान को खतरे में डालने का इरादा रखती है। उन्होंने मतभेदों और संघर्षों को हल करने के लिए गारंटीकृत उपाय के रूप में अहिंसा को प्रोत्साहित किया। तिब्बत के अंदर चीन के निरंतर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करते हुए इस मुद्दे पर काम करने के लिए मेक्सिको में एक 'बड़ी टीम'के गठन को भी स्वीकार किया।

प्रतिनिधिमंडल के तीसरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए लिथुआनियाई संसद के सदस्य माननीय अरुणस वालिंस्कास ने सराहना करते हुए कहा,'यह देखना वास्तव में आकर्षक है कि निर्वासन में तिब्बती लोगों ने कई चुनौतियों के बावजूद खुद को संगठित रखने और अपने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है।'उन्होंने आश्वस्त किया कि लिथुआनिया में तिब्बत मुद्दे को समर्थन देनेवाले अनेक संसदीय और गैर-संसदीय समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और बुद्धिजीवियों के अनेक समूह सक्रिय है। लिथुआनियाइयों और तिब्बतियों के बीच के संबंध को 'दिलचस्प'लेकिन 'अजीब'बताकर दोनों के बीच की दूरी और अंतर को देखते हुए उन्होंने कहा, 'यदि आप (संबंधों) के बारे में गहराई से सोचते हैंतो यह अजीब नहीं लगता है क्योंकि हमारे राष्ट्रों ने इसी तरह के परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया हैं।'उन्होंने आगे कहा,'उत्पीड़न का शिकार होना हमें समान बनाता है।'

सभी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के संबोधन के बादवक्ताओं ने संयुक्त प्रेस बैठक में इकट्ठे हुए तिब्बती और भारतीय मीडिया घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।

परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर तीनों ने सर्वसम्मति से चीन के हस्तक्षेप की निंदा की। अरुणस वालिंस्कास ने परम पावन के पुनर्जन्म के मुद्दे को 'धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की आवाज के व्यापक सिद्धांतों'के रूप में रेखांकित किया, चाहे वह पुनर्जन्म की मान्यता हो या तिब्बतियों के अपने धर्म का पालन करने का मामला। उसी समय, सल्वाडोर कारो कैबरेरा ने इस मामले पर वैश्विक समुदाय से ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि मिकुलस पेक्सा ने परम पावन और सीटीए को वर्तमान दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने के लिए वैध प्राधिकारी बताया।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मीडियाकर्मियों द्वारा यूरोपीय संघ में तिब्बत के लिए एक विशेष समन्वयक नियुक्त करने की संभावना, चीन की घरेलू राजनीति में उलटफेर और तिब्बत और व्यापक दुनिया पर इसके नतीजों के बारे में सवालों के जवाब दिए। उन्होंने तिब्बत और चीन के बीच संवाद होने की स्थिति में उसकी प्रामाणिकता के संबंध में उठाए गए विभिन्न सवालों के भी जवाब दिए। प्रतिनिधिमंडल के तीन प्रतिनिधियों ने भी परम पावन के साथ मुलाकात के अपने-अपने अनुभवों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बती जनक्रांति दिवस की चौसठवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज के आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेकर चीन को दिया जानेवाला संदेश भी दे दिया।

◆ चेक विदेश मंत्री लिपावस्की ने भारत यात्रा के दौरान चीन-तिब्बत संघर्ष और आपसी व्यापार पर चर्चा की

brnodaily.com, ०२ मार्च, २०२३

दिल्ली, २८ फरवरी (सीटीके)। चेक विदेशमंत्री जान लिपावस्की ने आज ०२ मार्च को अपनी भारत यात्रा के दौरान तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और डब्ल्यूआईओएनसमाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन की आक्रामक कार्रवाइयों पर टिप्पणी की।

लिपावस्की ने ट्विटर पर लिखा कि भारत यात्रा के दौरान निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें खुशी हुई।साथ ही यह भी कहा कि दिवंगत चेक राष्ट्रपति वाक्लेव हावेल और दलाई लामा के बीच दोस्ती अभी भी जीवित है।

चीन का दावा है कि उसने तिब्बत को मुक्त कराया और इसके आर्थिक विकास को वित्तपोषित करके इसके निवासियों के जीवन में सुधार कर रहा है।लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि बीजिंग स्थानीय लोगों, भाषा और संस्कृति का दमन कर रहा है।

लिपावस्की ने डब्ल्यूआईओएनको बताया कि चीन और उसकी आर्थिक ताकत प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह एक सैन्य महाशक्ति बन रहा है और हमें इससे निपटने के तरीकों की तलाश करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारत इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। मुझे लगता है कि यूरोप इसे अच्छी तरह समझता है। और निश्चित रूप से, अमेरिका इसे बहुत अच्छी तरह से समझता है। हमें उस पर सहयोग करने और चीनियों से इस तरह से निपटने में सक्षम होने की आवश्यकता है,जिससे भविष्य में किसी भी संभावित संघर्ष से बचा जा सके।

जब लिपावस्की निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेन्पा छेरिंग से पिछले साल वाशिंगटन में मिले थेतो चीन ने इसकी तीखी निंदा की थी।चीन ने कहा था कि लिपावस्की तिब्बती अलगाववादी गतिविधि को अनुचित संदेश भेज रहे हैं।

साक्षात्कार में रक्षा उद्योग में संभावित सहयोग का भी उल्लेख किया गया। लिपावस्की ने कहा,'यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध से पता चलता है कि रूसी सेना विश्वसनीय भागीदार नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा रक्षा उद्योग है और हम इसे भारत के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। कुछ परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैंऔर हम उस तरह के सहयोग को बढ़ाने में सक्षम होना चाहते हैं।'

भारत ने कभी भी खुले तौर पर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है और मास्को के साथ गहन व्यापारिक संबंध बनाए रखा है। भारत

पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान के समय अनुपस्थित रहा,जिसमें कहा गया था कि रूस तुरंत यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाए।

लिपावस्की ने कहा कि उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य 'यह दिखाना है कि चेक गणराज्य सहयोग करने के लिए तैयार है, और हमारे पास पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है।'

लिपावस्की ने कहा,'हमारे पास महान विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास बड़ी कंपनियां हैं। हम रिसर्च और इनोवेशन के मामले में आपसी हित के संबंध बनाना चाहते हैं। स्कोडा या टाटा ट्रकों की बात करें तो हमारे पास एक बहुत मजबूत ऑटोमोटिव उद्योग है। हम यहां बने रहना चाहते हैंऔर हम इस संपन्न अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा,'उन्होंने यह भी कहा कि वह दो एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि प्राग भारत के लिए सीधी उड़ान के लिए तैयार हैं।'

लिपावस्की ने आज दिल्ली में 'यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव बिजनेस कॉन्फ्रेंस'में भाषण दिया, जिसमें भारत के विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य और भारत विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेलीहेल्थ, बायोमेडिसिन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में।

उन्होंने कहा कि चेक फर्मों ने स्मार्ट सिटी, कचरे के ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणा में सहयोग की पेशकश की है।

◆ तिब्बतियों ने पूरी दुनिया में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ मनाई

tibet.net, १० मार्च, २०२३

धर्मशाला। दुनिया भर में तिब्बतियों और तिब्बत के दोस्तों ने तिब्बती शहीदों का सम्मान करने और तिब्बत में भयावह स्थिति के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए ६४वां तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस मनाया।

तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के विरोध में शुक्रवार १० मार्च को सैकड़ों तिब्बती ब्रसेल्स की सड़कों पर उतर आए। दशकों से चली आ रहे चीनी अत्याचारों के विरोध में तिब्बती शुमन राउंडअबाउट में एकत्रित हुए,जिसे यूरोपीय क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर यूरोपीय आयोग और परिषद का मुख्यालय भी है।

प्रदर्शनकारियों को तिब्बती झंडे, परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें, १५७ आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों के चित्र, नारों वाले बैनर और राजनीतिक कैदियों के चित्र लिए हुए देखा गया।

बेल्जियम बुद्धिस्ट यूनियन के अध्यक्ष कार्लो लुइक, आईसीटी ब्रसेल्स के कार्लो लुइक, डेविड वैन डेर मेलेन, तिब्बत के सचिव थिनले वांगड्यू के कार्यालय के प्रतिनिधि और ब्रसेल्स में तिब्बती संघों के प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे।

सचिव थिनले वांगड्यू ने सभा को तिब्बत के राजनीतिक इतिहास में १० मार्च के महत्व के बारे में याद दिलाया। उन्होंने बताया कि १० मार्च ने अतीत के तिब्बतियों और वर्तमान के तिब्बतियों के जीवन को छुआ है। उन्होंने टिप्पणी की, 'यह दिन तिब्बती लोगों की पीढ़ियों में साहस, लचीलापन और आशा का संचार करता है और तिब्बती मुक्ति साधना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।'

सभा में भाषण के बादप्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए चीनी दूतावास की ओर मार्च किया।

इस विरोध-प्रदर्शन का सह-आयोजन बेल्जियम के तिब्बती समुदाय, द इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत और हाइकिंग फार चिल्ड्रेन ने किया था।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगभग ७५० तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों ने फ्रीडम ग्राउंड से चीनी दूतावास तक शांति-मार्च निकाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथिजीन ल्यूक रोमेरो मिशेल (एडज्वाइंट ए ला मैरी डे पेरिस) ने मार्च के प्रतिभागियों को संबोधित किया, जहां तिब्बती संघ के सचिव और शिक्षा निदेशक ने सामूहिक रूप से १० मार्च के बड़े आयोजन में फ्रांस के ११० तिब्बती निवासियों की भागीदारी को स्वीकार किया। विरोध- प्रदर्शन यूरोप के सभी तिब्बत समर्थक संघों द्वारा रोम में आयोजित किया गया।

ब्रसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के निर्देशों के अनुसार, पेरिस में ब्यूरो डु तिब्बत ने भी फ्रांस के अंदर ६७१ क्षेत्रों में तिब्बती राष्ट्रीय झंडे भेजे हैं और उनसे १० मार्च के दौरान झंडे फहराने की अपील की है और कई लोगों ने सहमति भी दी है। एक क्षेत्र ने तिब्बतियों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया और १० मार्च तिब्बती जनक्रांति दिवस के स्मरणोत्सव के लिए एक समारोह आयोजित करना सुनिश्चित किया है।

जापान में तिब्बती समुदाय और फ्री तिब्बत जापान चैप्टर के छात्रों ने संयुक्त रूप से तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक शांति मार्च का आयोजन किया।

टोक्यो में एक वार्ता समारोह आयोजित किया गया,जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया। प्रतिनिधि डॉ आर्य छेवांग ग्यालपो ने प्रतिभागियों को उनके निरंतर समर्थन और इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जापानी भाषा में कशाग के बयान का सार पढ़ा और सभी प्रतिभागियों को पूरा बयान वितरित किया गया।

प्रतिनिधि आर्य ने 'तिब्बत नीड्स योर हेल्प (तिब्बत को आपकी सहायता की आवश्यकता है)'शीर्षक पुस्तक का विमोचन एवं वितरण किया। पुस्तक में चीनी आवासीय विद्यालयों में तिब्बती बच्चों को जबरन शिक्षित करने, तिब्बती धार्मिक वस्तुओं को नष्ट करने और १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म सहित प्रमुख तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म के चयन में सीसीपी के हस्तक्षेप के माध्यम से तिब्बती पहचान को मिटाने के लिए चल रही चीनी नीति का विवरण दिया गया है। उन्होंने तिब्बती धार्मिक मामले में सीसीपी के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए एक बयान जारी करने के लिए जापानी सांसदों के द्विदलीय सुपर संघ को धन्यवाद दिया। इसके अलावा, उन्होंने जापान के तिब्बत समर्थन समूह और जापान बौद्ध सम्मेलन को उनके बयान के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें तिब्बत में चीन द्वारा लगातार दमन और मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा की गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि जापानी संसद, समर्थक समूहऔर गैर सरकारी संगठन बढ़ते चीनी अतिक्रमण और तिब्बती संस्कृति, भाषा और पहचान के उन्मूलन को रोकने के लिए इसी तरह के बयान जारी करें।

स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत (एसएफटी) जापान के छेरिंग दोरजी ने चीनी बोर्डिंग स्कूलों में युवा तिब्बती बच्चों की जबरन शिक्षा पर बात की और तिब्बती बच्चों से उनकी मातृभाषा और पहचान के मौलिक अधिकार को छीनने के लिए सीसीपी की निंदा की। उन्होंने कहा कि एसएफटी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर काम करेगी ताकि चीन को तिब्बती भाषा के उन्मूलन से रोका जा सके।

तारो कणाडा ने सुपर संघ समूह के बयान को पढ़ा, जहां संघ के सदस्यों ने तिब्बत में चीनी दमन की निंदा की और यह स्पष्ट किया कि सीसीपी को तिब्बती धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तिब्बति लामाओं के पुनर्जन्म के चयन के अधिकार का दावा करना बंद कर देना चाहिए। लामाओं में १५वें दलाई लामा भी शामिल हैं।
सत्य वचन (डेंट्सिग मोनलम) प्रार्थना का जाप और तिब्बती जनक्रांति गीत (मीमांग लांगलू) का गायन वीडियो फुटेज के साथ किया गया।

आधिकारिक वार्ता समारोह के बाद लगभग १०० तिब्बतियों और जापानी, उग्यूर, चीनी और दक्षिण मंगोलियाई समर्थकों ने नारे लगाते हुए और तिब्बती झंडे और तख्तियां लेकर शिबुया शहर की सड़क पर शांति मार्च निकाला। शांति मार्च ने सड़क पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ जापानी और विदेशी भी विरोध मार्च में शामिल हुए और तिब्बत के लिए अपना समर्थन जताया।
शांति मार्च टोक्यो में चीनी दूतावास की ओर बढ़ रहा थाजहां मुक्त तिब्बत, मानवाधिकार और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में नारे लगाए गए। दूतावास के लेटर बॉक्स में तिब्बत में चीनी उत्पीड़न तत्काल रोकने से संबंधित बयान और कशाग का बयान डाल दिया गया।
उत्तरी अमेरिका में तिब्बतियों के ३० विभिन्न संघों ने तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के सांसदों को आवेदन भेजकर हाल ही में पेश किए गए द्विसदनीय तिब्बत विधेयक जो तिब्बत-चीन संघर्ष अधिनियम (एच.आर. ५३३, एस.१३८) के नाम से पेश हुआ है,को पारित कराने को समर्थन करने की अपील की है।
इसके अलावातिब्बती संघों के नेतृत्व में तिब्बती और समर्थक तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के सहयोग सेपरेड, प्रदर्शन, तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराने सहित विभिन्न अभियानों का आयोजन करते रहते हैऔर तिब्बत के अंदर चीन की दमनकारी नीतियों को लागू करने के बारे में श्रोताओं को सूचित करने के लिए तिब्बत मुद्दे की वकालत करते रहते है। सभाओं में कशाग और निर्वासित तिब्बती संसद के बयान भी पढ़े गए। सभाओं को अतिथियों और तिब्बती प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।
कुल्लू में तिब्बती समुदाय ने सीटीए के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत संग्रहालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफिक प्रदर्शनी की मेजबानी करके इस घटना को याद किया। प्रदर्शनी में तिब्बत के इतिहास और वर्तमान स्थिति को चित्रित करने वाले फोटोग्राफिक आख्यान को दर्शाया गया।
भारत की राजधानी दिल्ली में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ के आधिकारिक स्मरणोत्सव में मुख्य अतिथि श्री संजय सिंह (सांसद, राज्यसभा) और विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि लोबसांग शास्त्री (परम पावन दलाई लामा के दिल्ली ब्यूरो) और श्री प्रह्लाद सिंह साहनी (विधायक) उपस्थित थे।
टीसीवी डे स्कूल समयेलिंग में सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने चीन जैसे खतरे को चुनौती देने के लिए अहिंसा को सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने बुद्ध शाक्यमुनि और परम पावन दलाई लामा को अहिंसा के पैरोकारों के रूप में मान्यता दी। सभा ने तिब्बती शहीदों की याद में एक मिनट का मौन रखा।
इसी तरह मुंडगोड तिब्बती सेटलमेंट कार्यालय के नेतृत्व में तिब्बतियों ने तिब्बती जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ पर आधिकारिक समारोह आयोजित किया।
इस में तिब्बती सांसद, स्थानीय तिब्बती विधानसभा के अध्यक्ष, सेटलमेंट अधिकारी, स्थानीय तिब्बती विधानसभा के सदस्य, तिब्बती मुक्ति साधना के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य, तिब्बती सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव, स्कूलों के प्रमुख, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, तिब्बती एलोपैथी और होम्योपैथी केंद्रों के प्रमुख और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
समारोह की शुरुआत वरिष्ठ स्कूल बैंड द्वारा जनक्रांति दिवस गीत के गायन के साथ हुई।इसके बाद भारतीय और तिब्बती राष्ट्रगान हुआ।तिब्बती शहीदों के लिए एक मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद संभूता स्कूल के छात्रों द्वारा प्रार्थना की गई।
सेटलमेंट अधिकारी ल्हाकपा डोल्मा ने कशाग का बयान पढ़ा, उसके बाद तिब्बती सांसद गेशे ल्हारम्पा अट्रुक छेतेन ने संसद का बयान पढ़ा।
समारोह का समापन तिब्बती समुदाय की सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ।
१० मार्च २०२३ की शाम लगभग ०६ बजे तिब्बती यूथ हॉस्टल हॉल में माननीय मुख्य अतिथि डॉ. मदन कृष्ण गोपाल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समापन कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
मुख्य अतिथि द्वारा घी के दीपक की रोशनी के साथ कार्यक्रम हुआ और उसके बाद तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान गाया गया। इसके बादतिब्बती शहीदों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। फिर सभी लोगों ने सर्वसम्मति से १० मार्च का स्मरणोत्सव गीत गाया और सीआरओ जिग्मे सुल्त्रिम ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कशाग का वक्तव्य पढ़ा। क्षेत्रीय तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के उपाध्यक्ष ने निर्वासित तिब्बती संसद का वक्तव्य पढ़ा। इसके तुरंत बादमुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण गोपाल जी ने अपने बहुमूल्य विचारों और दर्शनों से सभा को संबोधित किया है।
कार्यक्रम का समापन तिब्बती यूथ हॉस्टल, बेंगलुरु के निदेशक द्वारा सत्य वचनों की प्रार्थना और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ पर ग्रीनविच के रॉयल बरो के मेयर, पार्षद लियो फ्लेचर और ग्रीनविच के रॉयल बरो के नेता, पार्षद एंथनी ओकेरेके ने दक्षिण-पूर्वी लंदन स्थित ग्रीनविच रॉयल बरो के मुख्यालय वूलविच टाउन हॉल में तिब्बत का झंडा फहराकर तिब्बत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
लंदन में बरो के महापौर और नेता ने तिब्बती संघर्ष को मुक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में वर्णित किया और बरो में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लिए अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे भी इस दिन को स्थायी रूप से मनाने के लिए परिषद में इसके लिए प्रस्ताव पारित कराने का वादा किया। परम पावन दलाई लामा के उत्तरी यूरोप, बाल्टिक देशों और पोलैंड के लिए प्रतिनिधि के लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के कर्मचारी तेनज़िन ज़ेधन ने कार्यालय की ओर से कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने महापौर और नेता को इस महत्वपूर्ण समय में उनके निरंतर समर्थन और तिब्बतियों के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्हें तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति से भी अवगत कराया। ज़ेधन द्वारा महापौर और नेता को मित्रता और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज पिन बैज प्रदान किया गया। महापौर ने फिर सभी को रॉयल बरो ऑफ ग्रीनविच पिन बैज उपहार में दिया।
इस कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय के सदस्य, ग्रीनविच तिब्बतन एसोसिएशन के परिषद सदस्य, ब्रिटेन में तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष तेनज़िन कुंगा और ग्लोबल एलायंस फॉर तिब्बत एंड पर्सेक्यूटेड

माइनोरिटीज (तिब्बत और सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए वैश्विक गठबंधन)के संस्थापक और अध्यक्षछे रिंग पासांग शामिल हुए, जिन्होंने एसोसिएशन की ओर से तिब्बती झंडोत्तोलन समारोह का समन्वय किया।

ग्रीनविच तिब्बतन एसोसिएशन ने महापौर और नेता को पारंपरिक तिब्बती सफेद खटक भेंट कर महापौर कार्यालय को धन्यवाद दिया। सितंबर २०१५ में रॉयल बरो ऑफ ग्रीनविच के ओ२ सेंटर में परम पावन दलाई लामा के सम्मान और स्वागत करने के क्रम में तिब्बती ध्वज पहली बार इस इंग्लिश टाउन हॉल में फहराया गया था।

ताइवान की राजधानी ताइपे के लिबर्टी स्क्वायर में एक प्रार्थना सभा और कैंडललाइट विजिल (मोमबत्ती जुलूस) का आयोजन किया गया। वहां तिब्बत के लिए ताइवानी संसदीय समूह के उप महानिदेशक हंग सन-ह्यान,हक्का मामलों की परिषद के मंत्री यियोंग कैज़िन, न्यू पावर पार्टी से ताइवान के जनप्रतिनिधि वांग वांग यू, हांगकांग यूथ एसोसिएशन के प्रतिनिधि स्काईऔर ताइवान के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सन यू लियान ने अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए स्मरणोत्सव में भाग लिया।

किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा न हो,इसलिए ताइवान में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केलसांग ग्यालत्सेन बावा ने अपने संबोधन में जोर देकर स्पष्ट किया कि 'तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस का स्मरणोत्सव तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग नहीं करता है, बल्कि यह हर उस तिब्बती को सांकेतिक तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है,जिन्होंने बलिदान दिया है और तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से अब तक तिब्बत के मुद्दे के लिए कष्ट सहते आ रहे हैं।

ताइवान में तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष ताशी छेरिंग और ताइवान में एनजीओ के प्रमुख लिन सीनयी द्वारा इस कार्यक्रम की व्यवस्था की गई और इसे संभव बनाया गया।

हर एक वर्ष के अंतराल पर यूरोप के तिब्बती समुदाय यूरोप के शहरों में से किसी एक में 'यूरोप स्टेंड विद तिब्बत (यूरोप तिब्बत के साथ है)'कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस वर्षपूरे यूरोप के तिब्बतियों और यूरोपीय लोगों ने १० मार्च २०२३ को इटली की राजधानी रोम में ६४वें तिब्बत राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस को 'यूरोप स्टेंड्स विद तिब्बत'कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मनाया। अगला समारोह २०२५ में नीदरलैंड के एम्स्टर्डममें आयोजित किया जाएगा।

प्रदर्शन का आयोजन इटली के तिब्बती समुदाय द्वारा यूरोप में अन्य तिब्बती समुदायों- इटालिया-तिब्बत संघ, बुद्धिस्ट यूनियन ऑफ इटली, इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत- जर्मनी एंड यूरोप और स्विस-तिब्बतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के समर्थन से किया गया था। कई अन्य तिब्बत समर्थक समूहों ने भी इस आयोजन के लिए अपना समर्थन दिया।

प्रदर्शन लार्गो कोराडो रिक्की से शुरू हुआ और बाद में पियाज़ा डेला मैडोना डी लोरेटो में इकट्ठा हुआ। पूरे यूरोप से हजारों हजार तिब्बती और यूरोपीय प्रदर्शन में शामिल हुए।

प्रदर्शन में मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष तेखंग डोल्मा छेरिंग, तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुक्की , यूरोप से निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्टेन ग्यात्सो, फ्रांसीसी सीनेटर सुश्री एल्स जोसेफ, इतालवी सीनेटर एंड्रिया डी प्रिमो और इतालवी सांसद इलेनियो मालवसी के अलावा इटली में तिब्बत समर्थक समूहों के कई अन्य प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया।

सभा को संबोधित करती हुई उपाध्यक्ष तेखंग डोल्मा छेरिंग ने १९५९ से तिब्बतियों पर शुरू हुए अत्याचारों और कष्टों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर कब्जे के बाद से ६००० से अधिक मठ नष्ट कर दिए गए हैं और अनेक तिब्बती मारे गए हैं। उन्होंने कहा, 'चीन दुनिया को दिखा रहा है कि तिब्बत में सब ठीक है तो तिब्बत में तिब्बती खुद को क्यों जला रहे हैं।'तिब्बत में १५८ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। अब उनका डीएनए नमूना संग्रह के माध्यम से व्यापक निगरानी की जा रही है। उन्होंने दुनिया से तिब्बत के पक्ष में खड़े होने का आह्वान किया।

प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने तिब्बत के पक्ष में खड़े होने के लिए सभी समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और सरकारों से तिब्बत का समर्थन करने का आह्वान किया। फ्रांसीसी सीनेटर सुश्री एल्स जोसेफ ने तिब्बती मुद्दे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि तिब्बत के लिए फ्रांसीसी संसदीय समूह तिब्बती आंदोलन का समर्थन करना जारी रखेगा। इतालियन पॉर्लियामेंटरी इंटरग्रुप फॉर तिब्बत की समन्वयक एंड्रिया डी प्रामो ने कहा कि नवगठित इंटरग्रुप तिब्बत पर अपना समर्थन कार्य जारी रखेगा और तिब्बत के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने की दिशा में काम करेगा। इसी तरह इटली की सांसद इलेनियो मालवसी ने भी तिब्बत के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इटालिया तिब्बत एसोसिएशन के अध्यक्ष क्लाउडियो कार्डेली, इतिहासकार और अंतरराष्ट्रीय वकीलमाइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग, पूर्व इतालवी सांसद माननीय लुसियानो नोबिली, इतालवी बौद्ध संघ के अध्यक्ष फ़िलिपो सिआना और इंस्टीव्यूटो लामा छोंगखापा श्री वैलेरियो तालारियो ने भी सभा को संबोधित किया।

◆ भारत में तिब्बत समर्थक समूहों ने ६४वां तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस मनाया

tibet.net, १० मार्च, २०२३

नई दिल्ली। दुनिया भर के तिब्बतियों ने तिब्बती शहीदों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए १० मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ मनाई। ये तिब्बती १९५९ में इसी दिन तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एकत्रित हुए थे और तिब्बत पर कम्युनिस्ट चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ खड़े हो गए थे। भारत में भी तिब्बत समर्थक समूहों ने तिब्बती भाइयों के साथ मिलकर तिब्बती शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे का विरोध किया और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई।

दिल्ली मेंभारत-तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस)के महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती संध्या सिंह के नेतृत्व में इसके सदस्यों ने मजनुं का टीला स्थित समयेलिंग तिब्बती सेंटलमेंट कार्यालय द्वारा आयोजित ६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लिया। बीटीएसएस के सदस्य देहरादून, शिमला और मैनपाट में भी इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए तिब्बती भाइयों और बहनों के साथ शामिल हुए।

भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के महासचिव श्री पंकज गोयल और इसके सदस्य क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस, दिल्ली द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर १० मार्च को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम गंभीर भी तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना समर्थन और भावना व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित थे।

गुजरात के पाटन में बीटीएसएम ने इस अवसर पर आचार्य हेमचंद उत्तर

गुजरात विश्वविद्यालय में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। बीटीएसएम पश्चिमी क्षेत्र के समन्वयक श्री गजेंद्र कुमार जोशी ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन से लेकर तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के उत्पीड़न तक तिब्बत में किए गए अत्याचारों को दर्शाने वाली चीन की नीतियों की निंदा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे की निंदा करते हुए तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और प्रेस बयान जारी किया। आईटीएफएस बिहार के अध्यक्ष श्री हरेंद्र कुमार द्वारा संबोधित प्रेस बैठक में बड़ी संख्या में तिब्बत समर्थक शामिल हुए, जिसमें श्री सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रभात कुमार और विश्वानंद शामिल थे। सीतामढ़ी मेंआईटीएफएस के जिला अध्यक्ष डॉ. शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में आईटीएफएस सदस्यों ने एक कार्यक्रम सह बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने भारत सरकार से परम पावन दलाई लामा के दूतों और चीनी जनवादी गणराज्य के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता की जल्द बहाली के लिए चीन पर दबाव बनाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया।

भारत-तिब्बत मैत्री संघ ने झारखंड के अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार के नेतृत्व में हजारीबाग में, राजस्थान के जोधपुर में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेशमा बाला के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री अमृत बंसोड़ के नेतृत्व में भंडारा में और कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में आईटीएफएस के सदस्य तिब्बती भाइयों और बहनों के साथ इस दिवस को मनाने के लिए शामिल हुए।

असम के गुवाहाटी में 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'के संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता के नेतृत्व में गौहाटी प्रेस क्लब में ६४वां तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इस मंच की समन्वयक श्रीमती नोवनीता शर्मा द्वारा लिखित 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'पुस्तक का विमोचन किया गया। सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान तिब्बती स्वतंत्रता के लिए पूरी एकजुटता के साथ तिब्बती राष्ट्रगान भी गाया।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग मेंश्री ल्हुंडुप चोसांग के नेतृत्व में भारत-तिब्बत सहयोग मंच, भारत-तिब्बत मैत्री संघ और तवांग रंगडेन सोकचुंग ने इस महत्वपूर्ण दिन को मनाया। इस अवसर पर तवांग मठ से जनरल परेड ग्राउंड तक एक शांति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तवांग और उसके आसपास के एनजीओ और तिब्बत समर्थक शामिल हुए। इन लोगों ने कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के खिलाफ नारे लगाए और तिब्बत की आजादी के लिए आवाज उठाई।

भारत में तिब्बत समर्थक समूहों ने ६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के साथ-साथ१२ मार्च को ६४वां तिब्बती महिला क्रांति दिवस मनाया। समूहों ने भारत-तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस)के महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती संध्या सिंह और भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के महासचिव श्री पंकज गोयल के नेतृत्व में क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ, दिल्ली द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान के जोधपुरमें भारत-तिब्बत मैत्री संघ की महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती रेशम बाला की अध्यक्षता में संघ ने इस दिन को मनाया।

◆ तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए असम में जन आंदोलन पर 'फ्री तिब्बत! वॉयस फ्रॉम असम' पुस्तक का विमोचन

tibet.net, १३ मार्च, २०२३

गुवाहाटी, १३ मार्च २०२३।पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत समर्थक समूह ने १० मार्च २०२३ को ६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के अवसर पर असम के गुवाहाटी स्थित गौहाटी प्रेस क्लब में 'फ्री तिब्बत! वॉयस फ्रॉम असम'पुस्तक का विमोचन कराया। पुस्तक तिब्बत समर्थक समूह 'फ्री तिब्बत:ए वॉयस फ्रॉम असम'की समन्वयक श्रीमती नोवानिता शर्मा द्वारा लिखी गई है।'

'फ्री तिब्बत:ए वॉयस फ्रॉम असम'भारतीय नागरिकों के सबसे गतिशील नागरिक समाज आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा है। यह चीनी कम्युनिस्ट सरकार के अवैध कब्जे और जबरदस्त शासन से तिब्बत की आजादी का समर्थन कर रहा है। यह पुस्तक भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों को पूर्वोत्तर भारत में हो रहे इस जमीनी आंदोलन से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। यह पूर्वोत्तर भारत से लिखित और प्रकाशित तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पहली पुस्तक है। यह पुस्तक 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'द्वारा संचालित जन आंदोलन का हिस्सा है। यह भारत के तिब्बत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दृष्टिकोण से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ पहलुओं को सबके सामने लाती है।

६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की कार्यवाही 'फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम'के सदस्यों द्वारा तिब्बती राष्ट्रगान के गायन के साथ शुरू हुई। इसके बाद औपचारिक रूप से पुस्तक विमोचन समारोह हुआ,जिसमें प्रमुख लेखकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, मीडियाकर्मियों के साथ-साथ तिब्बत समर्थकों और मंच के सदस्यों ने भाग लिया।

'फ्री तिब्बत! वॉयस फ्रॉम असम' शीर्षक वाली पुस्तक का औपचारिक विमोचन पद्मश्री श्री अजॉय दत्ता (प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता),रूपम बरुआ (पर्वतारोही, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार), डॉ जगदींद्र रायचौधरी (लेखक और शिक्षाविद्), श्री प्रणॉय बोरदोलोई (पर्वतारोही और वरिष्ठ पत्रकार), श्री रामानुज दत्ता चौधरी (ब्यूरो प्रमुख, असम ट्रिब्यून), श्रीमती उर्वशी महंत (समाजसेवी) और श्री सौम्यदीप दत्ता (लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता, 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'संयोजक) द्वारा किया गया। श्रीमती कंकना दास (सदस्य, फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम') ने अपने समृद्ध विचार-विमर्श के साथ इस कार्यक्रम की मेजबानी की। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में तिब्बती जनक्रांति दिवस के बारे में परिचय दिया। उन्होंने तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले पूर्वोत्तर भारत के जमीनी स्तर पर आंदोलन को बढ़ाने में 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'के योगदान के बारे में भी संक्षेप में बात की।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने अपने उद्घाटन भाषण में इस पुस्तक विमोचन समारोह में आए सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने इस पुस्तक की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की जो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ-साथ 'फ्री तिब्बत-ए वॉयस फ्रॉम असम'के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में हो रहे जमीनी नागरिक समाज आंदोलन के प्रत्यक्ष विवरण से परिपूर्ण है। उन्होंने कम्युनिस्ट चीन के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा

किया, जिन्हें इस पुस्तक के माध्यम से बहुत साहसपूर्वक दुनिया के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह शायद पूर्वोत्तर भारत से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखी गई पहली पुस्तक है।

श्रीमती नोवनीता शर्मा ने उद्घाटन भाषण के बाद पुस्तक के बारे में संक्षेप में बात की और प्रत्येक भारतीय नागरिक से पूरे दिल से तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने तिब्बती मुद्दे के प्रति भारतीयों से अपनी मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक शेष भारत और दुनिया को पूर्वोत्तर भारत के जमीनी आंदोलन से जोड़ेगी, जो तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही है। उन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को भारत का अभिन्न मुद्दा बताया और प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपने समर्थन और भागीदारी के साथ इस आंदोलन को मजबूत करने का आग्रह किया।

श्री रामानुज दत्ता चौधरी ने तिब्बत में कम्युनिस्ट चीनी सरकार से ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को उत्पन्न पारिस्थितिकीय खतरों के बारे में बात की।उन्होंने भविष्य में स्वतंत्रता के लिए तिब्बती खोज के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी बात की। श्री अजॉय दत्ता ने प्राचीन काल से तिब्बत और भारत के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने फ्री तिब्बत-असम में तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व करने में एक आवाज के गतिशील योगदान की प्रशंसा की। श्री प्रोनॉय बोरदोलोई ने भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत और पूरी दुनिया के लिए तिब्बती पठार के महत्व पर प्रकाश डाला। एक उत्साही पर्वतारोही के रूप में उन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिया और सभी से इस आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया।

डॉ. जगदींद्र रायचौधरी ने छात्रों और युवा पीढ़ियों के बीच तिब्बत और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस संबंध में 'फ्री तिब्बत- ए वॉयस फ्रॉम असम'के गतिशील कार्य की सराहना की। श्री रूपम बरुआ ने भारत की हिमालयी सीमाओं में शांति बहाल करने के लिए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत सदियों से भारत का पड़ोसी रहा है। तिब्बत हमारा वास्तविक पड़ोसी है।कम्युनिस्ट चीन ने १९५९ से तिब्बत पर जबरन कब्जा करके इस ऐतिहासिक सत्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने सीसीपी (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी) के दमनकारी शासन से तिब्बत के स्वतंत्र होने को लेकर अपना सकारात्मक विश्वास व्यक्त किया, बात अब सिर्फ समय की है।

श्रीमती उर्वशी महंत ने भारत के भविष्य की सुरक्षा और शांति के लिए तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व के बारे में संक्षेप में बात की। उन्होंने कहा कि 'फ्री तिब्बत! वॉयस फ्रॉम असम'शीर्षक पुस्तक का तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में समृद्ध योगदान है। उन्होंने सभी से इस पुस्तक को पढ़ने और भारत में इस नागरिक समाज आंदोलन को मजबूत करने के लिए इससे जुड़ने का आग्रह किया।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने कार्यक्रम का समापन किया और ६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस और पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आयोजन स्थल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों और आयोजकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान के बाद तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने कार्यक्रम का समापन किया और ६४वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस और पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आयोजन स्थल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों और आयोजकों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद भारतीय राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

◆ ताइवान में सैकड़ों तिब्बत समर्थकों ने तिब्बत के लिए शांति रैली निकाली

tibet.net, ०६ मार्च, २०२३

ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे में तिब्बती समुदाय और तिब्बत के दोस्तों ने कल ०५ मार्च को ताइपे में १० मार्च के तिब्बती जनक्रांति दिवस को मनाया।

इस समारोह में नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों सहित लगभग ६०० तिब्बत समर्थक शामिल हुए। विरोध सभा की अध्यक्षता प्रतिनिधि केलसांग ग्यालत्सेन बावा, तिब्बत के लिए ताइवानी संसदीय समूह की अध्यक्ष फ्रेडी लिम, उपाध्यक्ष सन हान हंग, ताइवान के राजनेता मियाओ पोया और लिन लियांगजुन ने की।

अधिकारियों ने तिब्बत के अंदर व्यापक मानवाधिकारों की स्थिति और तिब्बती जनक्रांति दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए काफी विस्तार से बात की।

सभा तिब्बत के अंदर आजादी के नारे लगाते हुए शहर के चारों ओर एक शांतिपूर्ण रैली में बदल गई और आगे बढ़ी।

तिब्बती मानवाधिकार समूह द्वारा ०८ फरवरी से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद १० मार्च को घटित घटना की याद में अभियान शुरू किया गया। प्रत्येक बुधवार को समूह ताइपे और कासोशिंग शहर के बीच साइकिल रैलियों का आयोजन करेगा।

०३ मार्च को प्रतिनिधि केलसांग ग्यालत्सेन बावा, फ्रेडी लिम, सांसद वांग वान्यू, सांसद लियू शिन-फांग, और तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष ताशी छेरिंग ने १० मार्च के स्मरणोत्सव के बारे में एक प्रेस वार्ता शुरू की, जिसे ताइपे की मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया था। उसी दिन प्रतिनिधि बावा और ताशी छेरिंग ने एक वार्ता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने तिब्बत में मौजूदा गंभीर स्थिति और अन्य विषयों पर सीटीए के राजनीतिक रुख और प्रयासों के बारे में बात की।

◆ चीन के साथ संबंधों पर यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की नजर तिब्बत के ताजा घटनाक्रम पर

tibet.net, ०७ मार्च, २०२३

ब्रसेल्स। चीन के साथ संबंधों पर यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल(डी-सीएन) ने सोमवार०६ मार्च को कोविड-१९ प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अपनी पहली आमने-सामने की बैठक में तिब्बत पर ध्यान केंद्रित किया। यह भी हाल के दिनों में पहली बार है, जब प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत के वर्तमान घटनाक्रमों पर चर्चा करने का निर्णय लिया है।

प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग, सैन फ्रांसिस्को स्थित गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में सोमपोंग सुचरितकुल सेंटर फॉर एडवांस्ड इंटरनेशनल लीगल स्टडीज में सीनियर फेलो और क्रेड्डा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ.वैन वाल्ट

वैन प्रागऔर इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज (द हेग) में इनेक्वलिटी,सोशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट (असमानता, सामाजिक संरक्षण और विकास) विभाग के प्रोफेसरएम. फिशर को इस मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था।

प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सांसद रेइनहार्ड बुटिकोफ़र ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि हाल के दिनों में यूरोपीय संसद पूर्वी-तुर्किस्तान,हांगकांग और ताइवान की स्थिति पर अधिक ध्यान दे रही है। लेकिन तिब्बत की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

डेढ़ घंटे के विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों को तिब्बत के ताजा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें तिब्बती पहचान को खत्म करने के उद्देश्य से इसके तीन प्रतीकों- भाषा, संस्कृति और धर्म को अपने में आत्मसात करने वाली चीन की नीतियों को लागू करना शामिल है। यह तिब्बत में सांस्कृतिक संहार के बराबर है। इसके अलावा तिब्बती बौद्ध धर्म का चीनीकरण, परम पावन दलाई लामा का उत्तराधिकार तय करने पर दावा और जबरन श्रम करवाने की घटनाएं शामिल हैं।

तिब्बत में बिगड़ती स्थिति को देखवक्ताओं ने यूरोपीय संघ से तिब्बत के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति के द्वारा समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया, जिसमें चीन से परम पावन दलाई लामा के दूतों के साथ एक ठोस बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया जाना शामिल है। चीन-तिब्बत संघर्ष के शांतिपूर्वक समाधान के लिए अन्य बातों के अलावा तिब्बत को अधिकृत देश के रूप में मान्यता देना होगा।

सम्मेलन में यूरोपीय संसद के सदस्यों, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के अधिकारियों, संसदीय सहायकों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और ब्रसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया।

◆ संयुक्त राष्ट्र निकाय ने तिब्बत में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन को माना और चीन को सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा

tibet.net, ०८ मार्च, २०२३

जिनेवा।आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की इस साल फरवरी के मध्य में आयोजित अधिवेशन की सिफारिशों का चीन द्वारा कार्यान्वयन की तीसरे दौर की समीक्षा के बाद संयुक्त राष्ट्र समिति ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र समिति ने चीन द्वारा तिब्बत, झिंझियांग, हांगकांग, मकाऊ और मुख्य भूमि चीन में भी अधिवेशन द्वारा निर्धारित दायित्वों के कार्यान्वयन में व्यापक उल्लंघन का उल्लेख किया है।

तिब्बती खानाबदोशों और छोटे किसानों का जबरन पुनर्वास और पुनर्स्थापना :

विशेषज्ञों ने खानाबदोश चरवाहों, विशेष रूप से तिब्बती चरवाहों के पुनर्वास के बारे में चिंता व्यक्त की है। यह पुनर्वासराज्य पार्टी में उचित परामर्श के बिना और ज्यादातर मामलों में मनमाने ढंग से, पूर्व सूचना दिए बिना और सहमति के बिना हो रहा है। इसी तरह छोटे किसान को उनकी संपत्ति के एवज में दिया जानेवाला मुआवजा पर्याप्त जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अक्सर अपर्याप्त होते हैं। इन छोटे किसानों की पारंपरिक भूमि और आजीविका खत्म हो गई है और इनका जीवन यापन गरीबी उन्मूलन योजनाओं और पारिस्थितिकीय बहाली पुनर्वास उपायों के भरोसे रह गए हैं।संयुक्त राष्ट्र समिति ने सिफारिश की है कि चीन ऐसे सभी जबरन पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यक्रमों को तुरंत रोक दे और पूर्ण, पर्याप्त और समय पर मुआवजे के साथ अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए उनके साथ सार्थक परामर्श करे।

श्रमिकों की स्थिति

तिब्बत में खराब कामकाजी परिस्थितियों, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की जांच के लिए श्रम निरीक्षण तंत्र की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र समिति ने चीन से सिफारिश की है कि वह तिब्बत में उल्लंघनकर्ता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रम निरीक्षण और स्वतंत्र ऑडिट संस्थाओं के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करे।

सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार:

संयुक्त राष्ट्र समिति ने तिब्बती भाषा, इतिहास और संस्कृति का उपयोग करने और पढ़ाने के अधिकार सहित तिब्बतियों द्वारा सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार पर प्रतिबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को नोट किया है। इसके अलावा, इसने तिब्बती भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूलों को बंद करने पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी द्वारा आत्मसात नीति के माध्यम से तिब्बती संस्कृति और भाषा को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। तिब्बती बच्चों पर चीनी स्कूली व्यवस्था थोपी गई है। इसे चीनीकरण करने के तौर पर देखा जा रहा है।

तदनुसार, संयुक्त राष्ट्र समिति ने चीन से अनिवार्य आवासीय विद्यालय प्रणाली को समाप्त करने और निजी तिब्बती स्कूलों की स्थापना की अनुमति देने का आह्वान किया है। इसके अलावा, इसने चीन को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की सिफारिश की है कि तिब्बती सांस्कृतिक जीवन, पहचान और साधना के अपने अधिकार और तिब्बती भाषा का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

धार्मिक स्वतंत्रता:

संयुक्त राष्ट्र समिति ने धार्मिक रीति-रिवाजों पर तेजी से सख्ती और तिब्बत में मठों सहित धार्मिक स्थलों के व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर विनाश के बारे में अपनी चिंताओं को नोट किया है। समिति ने सिफारिश की है कि चीन 'सांस्कृतिक विविधता और तिब्बतियों की सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और विरासत की रक्षा'के लिए पर्याप्त उपाय करे जिसमें धार्मिक स्थलों की रक्षा और पुनर्स्थापना शामिल है।'

जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो ने समीक्षा में भाग लिया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। समापन टिप्पणियों का स्वागत करते हुए प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने उल्लेख किया है कि 'चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन को संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्यों द्वारा स्पष्ट रूप से नोट किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि चीनी सरकार संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा अनुशंसित सुधारात्मक कार्रवाई करेगी। संयुक्त राष्ट्र के निकाय को यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि इसकी सिफारिशों को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाए बल्कि चीनी सरकार द्वारा इसे सार्थक रूप से लागू किया जाए।'

◆ ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चस्तरीय खंड में 'तिब्बत में स्वतंत्रता' पर चिंता व्यक्त की

tibet.net,०८ मार्च, २०२३

धर्मशाला।०१ मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चस्तरीय खंड में ऑस्ट्रेलिया के सहायक विदेशमंत्री टिम वाट्स द्वारा दिए गए एक बयान में उन्होंने तिब्बत में शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंता व्यक्त की। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया में तालिबान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
सहायक विदेश मंत्री टिम वाट्स ने अपने बयान में कहा,'ऑस्ट्रेलिया मानता है कि किसी भी देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड सही नहीं है। लेकिन साथ ही कोई भी देश अपने मानवाधिकार दायित्वों की निष्पक्ष जांच से ऊपर नहीं है। इस मामले में जहां हम पिछड़ते हैं, वहां स्थिति को स्वीकार करके उन्हें बेहतर करने का कठोर प्रयास करते हैं,न कि संदेशवाहक पर हमला करते हैं।'

उन्होंने एक ऐसी शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया के निर्माण का सामान्य लक्ष्य बताया,जहां हर व्यक्ति को अपने मानवाधिकारों का आनंद लेने की अनुमति होगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों और सभी देशों को भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने का निमंत्रण दिया।

◆ तिब्बत के लिए नवगठित इतालवी संसदीय इंटरग्रुप का इतालवी सीनेट भवन में शुभारंभ

tibet.net, ०८ मार्च, २०२३

रोम। तिब्बत के लिए नवगठित इतालवी संसदीय इंटरग्रुप का शुभारंभ तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर ०९ मार्च २०२३ को इतालवी सीनेट हॉल में होगा। तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की ६४वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रोम में १० मार्च को आयोजित होने वाले 'यूरोप स्टैंड्स विद तिब्बत'विरोध मार्च की घोषणा करने के साथ-साथ इंटरग्रुप के शुभारंभ की घोषणा करने के लिए सीनेट में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इंटरग्रुप के शुभारंभ की घोषणा के लिए ०८ मार्च को प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखंग, तिब्बत ब्यूरो जिनेवा में परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि थिनले चुक्की, यूरोप से निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्टेन ग्यात्सो के साथ इंटरग्रुप के को-ऑर्डिनेटर सीनेटर डी. प्रामो एंड्रिया और इंटरग्रुप के सदस्य सीनेटर टेर्ज़ी डी. संत अगाटा गिउलिओ, चैंबर ऑफ डिप्टी के सदस्य मालावासी इलेनिया, सीनेटर डोमेनिका स्पिनेली और इंटरग्रुप के पूर्व समन्वयक लुसियानो नोबिली उपस्थित थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इटालिया-तिब्बत एसोसिएशन के अध्यक्ष क्लाउडियो कार्डेली और इटली के तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष छेतेन बर्गामो ने सभा का स्वागत किया। इंटरग्रुप की को-ऑर्डिनेटर सीनेटर डी. प्रामो एंड्रिया ने इंटरग्रुप के महत्व का उल्लेख किया और पूर्व के इंटरग्रुप के कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने तिब्बत पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पारित होने के साथ-साथ संसद में तिब्बत की स्थिति को उजागर करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इंटरग्रुप के सदस्य सीनेटर टेरी डी. संत अगाटा गिउलिओ, माननीया मालवसी इलेनिया और इंटरग्रुप के पूर्व समन्वयक लुसियानो नोबिली ने भी प्रतिबद्धता दोहराई और चीनी सरकार के शासन के तहत तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के बारे में विस्तार से बात की।

प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और तिब्बत के लिए इतालवी संसदीय इंटरग्रुप के सफल गठन पर सांसदों को बधाई दी। तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस और तिब्बत की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण देते हुए उन्होंने इटली के तिब्बती समुदाय को 'यूरोप स्टैंड विद तिब्बत'कार्यक्रम के आयोजन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष डोल्मा छेरिंग तेखंग ने तिब्बत में बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि कम्युनिस्ट चीनी शासन व्यवस्थित रूप से तिब्बती संस्कृति, धर्म, भाषा और पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहा है। तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जमीनी हकीकत पर विस्तृत शोध कराने का आग्रह किया। इन औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन चीनी हान संस्कृति में विलीन कराया जा रहा है।उन्होंने आगे तिब्बती पठार के महत्व के बारे में बात की और कहा कि अत्यधिक खनन सहित गलत जानकारी वाली चीनी सरकार की नीतियां तिब्बत के नाजुक वातावरण को नष्ट कर रही हैं,जिससे ग्लोबल वार्मिंग गंभीर रूप से तेज हो रही है। इस संबंध में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बती पठार और उसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संयोजन के लिए चीन पर दबाव बनाने का आग्रह किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यूरोप से निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्टेन ग्यात्सो ने कहा कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से एक संप्रभु राज्य रहा है और तिब्बत पर आक्रमण और कब्जा एक अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता और तिब्बत ब्रीफ २०-२० पुस्तक के लेखक माइकल वान वाल्ट वान प्राग ने भी तिब्बत की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसकी कानूनी स्थिति के बारे में गहरी बातें बताई हैं। इतालवी बौद्ध संघ की अध्यक्ष साइना फ़िलिपो ने भी तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में बात की और बताया कि कैसे तिब्बत में तिब्बतियों के धार्मिक अधिकारों को चीनी सरकार द्वारा दबाया जा रहा है।
१० मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के ६४वें स्मरणोत्सव के अवसर पर तिब्बती समुदायों के लगभग १००० तिब्बती और यूरोप भर के तिब्बत समर्थन समूहों के 'यूरोप स्टैंड विद तिब्बत'कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है।

◆ तिब्बत हाउस ब्रासिल और यूआरआईआई ने संयुक्त रूप से शांति के लिए विज्ञान और धर्म के उपयोग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की

tibet.net, ०२ मार्च, २०२३

रियो डी जनेरियो।वैज्ञानिक पद्धति के लिए सामान्य अंतर-धार्मिक मूल्य को उजागर करने के लिएशांति के लिए विज्ञान और धर्म के उपयोग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन २३ फरवरी २०२३ को ब्राजील के यूनिवर्सिटी फेडरल एबीसी, सैंटो आंद्रे में आयोजित किया गया। इसका आयोजन यूनाइटेड रिलिजन इनिशिएटिव (यूआरआई) इंटरनेशनल क फादर डॉ. एच.सी. फिलिप रिबेरो जैन, सीसीएनएच-यूएफएबीसी की डॉ. मारिलिया मेलो पिसानी ने तिब्बत हाउस ब्रासिल के सहयोग से किया।

सम्मेलन में मुख्य वक्ता तिब्बती बौद्ध धर्म के सम्मानित,परम पावन दलाई लामा के पूर्व अनुवादक और नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी डमदुलथे। सम्मेलन में शामिल हुए अन्य प्रतिभागियों में इस्लामिक हिस्ट्री चैनल एफएएमबीआरएएस से मंसूर पेइक्सोटो,एंड्रे लुइस स्पिरिटिस्ट फाउंडेशन से अफोंसो मोरेरा जूनियर,अफ्रीकी धर्म संघ एफओईएसपी से टाटा माता मोरिडे,यहूदी संशयवादी,यूएफएबीसी में विज्ञान के दार्शनिक लुसियाना ज़टेरका और क्वेकर यूनिटेरियन यूनिवर्सलिज्म के फादर फेलिप रिबेरो जैन प्रमुख थे।

तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की ६४वीं वर्षगांठ पर कशाग का वक्तव्य
Dharamsala, 10th March 2023

आज १० मार्च को ठीक ६४ साल पहले इसी तारीख को १९५९ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के कब्जे के खिलाफ तिब्बती लोगों का विद्रोह हुआ था। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में लगातार तीन साल तक इस तारीख को हिंसक प्रदर्शन होने के बाद आज ही के दिन ३४ वर्ष पहले १९८९ में पीआरसी द्वारा तिब्बत में पहली बार मार्शल लॉ लागू किया गया था। और १५ वर्ष पहले २००८ में आज ही के तिब्बत के तीन पारंपरिक प्रांतों में शांतिपूर्ण विद्रोह की ज्वाला दहक उठी थी। इसलिए इन तीन महत्वपूर्ण और पवित्र अवसरों की वर्षगांठ पर हम अपने हमवतनों और शहीदों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने तिब्बत के लिए बिना मोल लिए अपनी जान दे दी। हम उनके परिवार के सदस्यों और उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं जो अभी भी पीआरसी के कब्जे के दमनकारी शासन से पीड़ित हैं।

हम श्री मिकुलस पेक्सा के नेतृत्व में चार-सदस्यीय यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, श्री सल्वाडोर कारो कैबरेरा के नेतृत्व में मेक्सिको के नौ-सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, तिब्बत समर्थन समूहों के सदस्यों, लिथुआनियाई संसद के सदस्य श्री अरुणस वालिंस्कास और नेशनल एनडॉमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष श्री डेमन विल्सन सहित अपने विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस महान अवसर पर हम तिब्बती लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए और राजनीतिक समर्थन के संकेत के तौर पर हमारे साथ शामिल होने वाले सभी लोगों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

चौसठ साल पहले इसी दिन को परम पावन १४वें दलाई लामा को ल्हासा के चीनी सैन्य मुख्यालय में एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। परंपरा के विरुद्ध जाकर परम पावन को सीमित संख्या में निहत्थे पहरेदारों के साथ शो में भाग लेने का आदेश दिया गया था। जब यह जानकारी तिब्बती लोगों तक पहुंची तो वे उबल पड़े और परम पावन दलाई लामा को शो में शामिल न होने और तिब्बत में पीआरसी सरकार द्वारा शुरू की गई दमनकारी नीतियों के खिलाफ सामूहिक विद्रोह शुरू कर दिया। खाम और अमदो में कुछ साल पहले लागू किए गए तथाकथित लोकतांत्रिक सुधारों की यादें अभी भी ताजा ही थीं, इसलिए विद्रोह शुरू हो गया। तिब्बतियों को सामूहिकता और करों को बढ़ाने के नाम पर उनकी भूमि, पशुधन और उत्पादन के साधनों को जब्त करके एक साथ भूमि सुधार और सहकारी व्यवस्था शुरू की गई थी। धार्मिक सुधार के नाम पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चीवर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और मठों को ध्वस्त कर दिया गया। जब तिब्बतियों ने विरोध किया तब लामाओं और आम नेताओं को धोखे से कैद कर लिया गया। तिब्बतियों पर 'दस्यु' और 'विद्रोही' का ठप्पा लगाकर उनका नरसंहार किया गया और उनका दमन किया गया। लगभग पिछले आठ वर्षों तक तिब्बतियों ने यह भी देखा था कि कैसे तिब्बत में पीआरसी नेतृत्व ने १७ सूत्रीय समझौते की शर्तों का घोर उल्लंघन किया था।

तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह ने परम पावन दलाई लामा और अन्य तिब्बती आध्यात्मिक और राजनीतिक नेताओं की चीनी सैन्य शिविर की यात्रा को टाल दिया और इस प्रकार इस घटना ने तिब्बती लोगों का भाग्य को बदल दिया। तिब्बत के देवताओं और दैवकृपा द्वारा संरक्षित और तिब्बती राष्ट्रीय सेना के सैनिकों और डेथ वॉलेंटियर आर्मी के चुशी गंगड्रुक रक्षकों द्वारा रक्षित परम पावन दलाई लामा ने कशाग के मंत्रियों के साथ स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित रूप से निर्वासन में जाने का रास्ता चुना। तिब्बती सरकार के अधिकारियों सहित लगभग ८०,००० तिब्बतियों ने उनका अनुसरण किया। इस निर्वासन में जाने के निर्णय ने तिब्बतियों की राष्ट्रीय पहचान को मिटाने के लिए पीआरसी सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास का विरोध करने के लिए तिब्बतियों में भावना और साहस के साथ अडिग नींव रखी।

चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के दौरान लगभग १२ लाख तिब्बती मारे गए, ६००० से अधिक मठों का विनाश हुआ और साथ ही वनों की कटाई और वन्य जीवन का विनाश और खनिज संसाधनों का दोहन हुआ। तिब्बत को हुए भारी विनाश से सबक सीखने में नाकाम पीआरसी के अधिकारी वही गलती दोहरा रहे हैं और यहां तक कि अपने अपराध को ढंकने के लिए आंख मूंदकर विनाशक कार्रवाई भी कर रहे हैं।

१९८० में देंग शियाओपिंग ने सुधार और खुलेपन की नीति को लागू करते हुए दो समग्र स्थितियों के आधार पर विकास पर अपनी रणनीतिक सोच को सामने रखा। पहला, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों की मदद से पूर्वी तटीय क्षेत्रों को खोलना और विकसित करना। दूसरे, तटीय क्षेत्र ने बदले में १९९० के दशक के अंत तक मध्यम समृद्धि के स्तर पर पहुंचने तक मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने में मदद किया। हालांकि, नई सहस्राब्दी की शुरुआत में तथाकथित पश्चिमी चीन विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत पश्चिम से बिजली पूरब को भेजना, वेस्ट-टू-ईस्ट गैस पाइपलाइन, किंघाई-तिब्बत रेलवे, रिटर्निंग फार्मलैंड टू फॉरेस्ट एंड ग्रासिंग टू ग्रासलैंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। वास्तव में ये औपनिवेशिक नीतियां हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार के बजाय पश्चिमी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। पचास

वर्षों की नियत अवधि के लिए कार्यान्वित किए जा रहे इन कार्यक्रमों को देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद ही ऐसी कोई परियोजना हो जो तिब्बत और तिब्बती लोगों की आजीविका के लिए वास्तव में लाभकारी हो। इसलिए देंग शियाओपिंग की विकास की रणनीतिक सोच एक खोखला नारा बनकर रह गई। इन नीतियों से न केवल चीन और तिब्बत के बीच संपत्ति की खाई चौड़ी हो गई है, बल्कि तिब्बती क्षेत्र और तिब्बती आज धनी चीनियों के लिए महज रूमानी वस्तु बन कर रह गए हैं। आज शी जिनपिंग आम समृद्धि की वकालत करते हैं, लेकिन इसे साकार होते देखने में कितना समय लगेगा, यह कहना किसी के लिए भी मुश्किल है।

चीनी राष्ट्र के लिए एकीकृत समुदाय की भावना को मजबूत करने के लिए पीआरसी सरकार वर्तमान में तिब्बती बौद्ध धर्म के चीनीकरण और पूरे तिब्बत में चीनी भाषा के प्रचार के माध्यम से एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक धर्म और एक भाषा की नीति को लागू कर रही है। तिब्बती बच्चों को चीनी भाषा और जीवन शैली सीखने के लिए औपनिवेशिक शैली के किंडरगार्टन और आवासीय स्कूलों के विशाल नेटवर्क में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। पीआरसी सरकार इन स्कूलों में सार्वभौमिक रूप से अपनाई गई शिक्षा प्रणाली और आंतरिक मानवाधिकार मानकों की पूरी अवहेलना करते हुए आत्मसातवादी भाषा नीति लागू कर रही है। इस वर्ष ०६ फरवरी को अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने आवासीय विद्यालय प्रणाली के माध्यम से १० लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप से आत्मसात करने की पीआरसी सरकार की नीति के खिलाफ चेतावनी दी है। २०२१ में प्रकाशित तथाकथित तिब्बत स्टैटिस्टिकल ईयर बुक में २००० में ४४९१ प्री-प्राइमरी चिल्ड्रेन स्कूल दर्शाए गए हैं, जो २०१० में तेजी से बढ़कर २३,४१४ और २०२० में १,५०,९३४ हो गए हैं।

आत्मसातिकरण में तेजी लाने के लिए तिब्बतियों और चीनियों के बीच विवाह को 'जातीय सद्भाव के मॉडल परिवार' के रूप में बढ़ावा देकर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इसी तरह, हजारों तिब्बती बच्चों को चीनी क्षेत्रों में तथाकथित तिब्बती स्कूलों में भेजा जा रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर युवा तिब्बतियों को दिहाड़ी मजदूरों के रूप में चीनी अधिकारियों के नियंत्रण में भेजा जा रहा है और चीन से काम करने वाली टीमों को तिब्बती क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा, चोन काउंटी और बत्से काउंटी के ५५७० तिब्बती निवासियों को उनके क्षेत्रों में बांध निर्माण और जल संरक्षण के बहाने जबरन जियुझ्यान में गुआझोउ काउंटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए प्रवासन के नाम पर द्रुक्चू काउंटी में २२५७ परिवारों को लान्झो झिंकू में पुनर्स्थापित किया गया है। इसके अलावा, त्सो सिटी, थेवो काउंटी और चोन काउंटी में तिब्बतियों को स्थानांतरित किया जाना तय किया गया है। इसी तरह जल संसाधन मंत्रालय के तहत ग्यालमो न्गुलचू (सलवीन), न्यागचू (यालुंग) और ज़ाचु (मेकांग) नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के कारण १३,४१५ स्थानीय निवासियों को विस्थापित किया गया था। इसी तरह, नगाबा प्रिफेक्चर में १३,००० से अधिक तिब्बतियों को स्थानांतरित किया गया और ३००० से अधिक को विस्थापित करने की योजना है। तिब्बतियों का यह सामूहिक विस्थापन १९३० के दशक में कई दशकों में लाखों जातीय अल्पसंख्यकों के जबरन पुनर्वास की स्टालिन की नीति के बराबर है, जिसे १४ नवंबर १९८९ को सोवियत संघ (यूएसएसआर) के सर्वोच्च सोवियत द्वारा अवैध और आपराधिक दमनकारी कृत्य घोषित किया गया था।

इसी तरह, नागचू, नागरी और शिगात्से प्रिफेक्चरों के लगभग बीस काउंटियों से १,००,००० से अधिक तिब्बती खानाबदोशों को तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के गोंगकर काउंटी के दीनबुरी में निर्मित शहर नंबर चार में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह गंभीर संदेह और आशंका पैदा करता है कि यह परियोजना कैसे विस्थापित लोगों के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करेगी और उनकी मूल भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

पीआरसी सरकार अलगाववाद का मुकाबला करने और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के नाम पर तिब्बतियों के हर आंदोलन को सांस्कृतिक क्रांति के समय से भी अधिक कठोर उपायों से नियंत्रित कर रही है। ग्रिड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नवीनतम तकनीक का उपयोग करके हर शहर, गांव, गली, चारागाह क्षेत्रों और घास के मैदानों का लगातार सर्वेक्षण किया जाता है। पिछले महीने टीएआर में एक तथाकथित 'नेटवर्क और सूचना सुरक्षा पर विनियम' लागू हुआ। इसने इंटरनेट की जानकारी की निगरानी और नियंत्रण के लिए काउंटी स्तर से ऊपर के सरकारी विभागों, राज्य और सार्वजनिक अंगों को काम सौंपा। विनियमन 'अलगाववादी ताकतों' के साथ सोशल मीडिया समूह बनाने और उसमें भाग लेने को भी अपराधी बनाता है। चीनी सरकार ने छात्रों, खानाबदोशों, किसानों सहित तिब्बतियों को जबरन बहकाने के अपने अभियान को तेज कर दिया है और सामाजिक प्रबंधन के नाम पर डीएनए सैंपल की जांच, आइरिस स्कैन और चेहरे की पहचान के माध्यम से भी किया जा रहा है।

पिछले साल मार्च में चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में पूर्वोत्तर तिब्बत में कीर्ति मठ के पास पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगाने के बाद ८१ वर्षीय तफुन की मृत्यु हो गई थी। वह २००९ के बाद से तिब्बत में आत्मदाह करने वाले १५७वें पुष्ट और ज्ञात तिब्बती बन गए। कशाग ने तिब्बतियों से फिर से अपील की कि वे तिब्बत मुक्ति साधना के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने के लिए अपने जीवन को संरक्षित रखें और आत्मदाह जैसे कदम न उठाएं।

तिब्बती लेखकों, बुद्धिजीवियों, भाषा अधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ताओं और पशु वध के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन गायब कर देने और न्यायेतर कारावास देने की अत्यधिक चिंताजनक खबरें तिब्बत से सामने आती रहती हैं। तिब्बती राजनीतिक कैदियों को खराब स्वास्थ्य की स्थिति में रिहा कर दिया जाता है और उन्हें निरंतर निगरानी में रखा जाता है। पिछले जुलाई में २००८ के तिब्बत व्यापी विरोध के दौरान गिरफ्तार किए गए एक पूर्व राजनीतिक कैदी जिग्मे ग्यात्सो की खराब स्वास्थ्य के कारण मृत्यु हो गई। एक अन्य पूर्व राजनीतिक कैदी गेशे तेनज़िन पलसांग, जिन्हें २०१२ में जेल की सजा सुनाई गई थी, का पिछले सितंबर में निधन हो गया। इसी बीच खबर के अनुसार, चीनी पुलिस ने एक वृद्धाश्रम से किराने का सामान चुरा कर ले जाने के आरोप में एक तिब्बती को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला। तिब्बतियों को सिर्फ धार्मिक कृत्य करने के लिए ही पीट-पीटकर मार डाला जाता है। साथ ही, परम पावन दलाई लामा की तस्वीरें रखने के लिए तिब्बतियों की गिरफ्तारी बेरोकटोक जारी है।

चीनी अधिकारियों द्वारा १९९५ में अपहरण कर लिए जाने के बाद से ग्यारहवें पंचेन लामा तेनज़िन गेधुन येशी थिनले, जिन्हें लोकप्रिय रूप से

गेधुन चोएक्यी न्यिमा कहा जाता है, का ठिकाना अज्ञात है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ग्यारहवें पंचेन लामा और अन्य तिब्बती राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखेगा। और सरकारों, मानवाधिकार संगठनों और व्यक्तियों से निरंतर समर्थन की अपील करता रहेगा। इस समर्थन अभियान में पहल करनेवाले सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं।

राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कानून है कि पूरे देश में क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पीपुल्स प्रोक्यूरेट्स के प्रमुख और उप मुख्य अभियोजक, राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों के पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्वायत्त क्षेत्रों प्रिफेक्चर और काउंटी के प्रमुख संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। हालांकि, तथाकथित टीएआर में काउंटी, प्रिफेक्चर और क्षेत्रीय स्तरों पर नेतृत्व में तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व बमुश्किल ४३% है। और यदि राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन जैसे शक्तिहीन निकायों में शामिल होने वाले लगभग ८०% तिब्बतियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो तिब्बती प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत कम होगा। टीएआर के समग्र नेतृत्व में लगभग १०% तथाकथित चीनी कैडर हैं जो चीन से तिब्बत की सहायता के लिए भेजे गए हैं। यह दर्शाता है कि पीआरसी सरकार तिब्बतियों को खुद पर शासन करने का कितना अधिकार देती है। इसी तरह, पिछले साल ही टीएआर में लगभग १३९ तिब्बती अधिकारियों पर जांच बिठाई गई और कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के बहाने निष्कासित कर दिया गया। बहुत से लोग इसे चीनी सरकार के स्थापित तंत्र के रूप में मानते हैं जिसका उद्देश्य सक्षम और होनहार तिब्बती अधिकारियों और तिब्बतियों के कौशल और क्षमता का गला घोंटना है। टीएआर के तथाकथित पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट की वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट ने १९९० से कुछ मामलों में जांच किए जाने की सूचना दी है। यह न्यायिक अभियोजन अवधि की पूरी तरह से अवहेलना है।

तिब्बत की राजधानी ल्हासा में लागू शून्य-कोविड नीति के तहत पिछले साल १०० से अधिक दिनों तक लगातार गंभीर लॉकडाउन रखा गया था, जिससे लोगों के दैनिक जीवन में भारी कठिनाई हुई। इससे कुछ लोगों को आत्महत्या तक करना पड़ा था। कुछ को वहां की वस्तुस्थिति और उनके ठिकाने के बारे में वीडियो और जानकारी बांटने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। तिब्बत से निकली जानकारी के मुताबिक, दिसंबर २०२२ में अचानक लॉकडाउन हटने के बाद चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई तिब्बतियों की मौत हो गई। यह बात इससे पता चली कि रोजाना बड़ी संख्या में शवों को श्मशान घाट ले जाते देखा जा रहा था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती समुदाय के कार्यालयों में मृतकों और महामारी से प्रभावित लोगों के लिए साप्ताहिक प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है।

जनता के लिए कल्याणकारी उपाय करना और लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करना सरकार की वैधता अर्जित करने की बुनियादी शर्त है। अत: यदि कोई सरकार किसी राष्ट्रीयता के उन्मूलन की नीतियों को खुल्लम-खुल्ला लागू करती है तो लोगों को सरकार की नीतियों का विरोध करने और यहां तक कि अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को नकारने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन इस संबंध में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण की नीति के आधार पर तिब्बत की भविष्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए परस्पर सहयोग का रास्ता खोजने की उम्मीद कर रहा है। हम समानता और मित्रता के आधार पर चीन सरकार के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी और स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके अलावा, हम चीन की सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तिब्बती पहचान को खत्म करने की अपनी त्रुटिपूर्ण नीति को तुरंत बंद कर दे।

हम फरवरी २०२३ में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल, सांसद जिम मैकगवर्न, सीनेटर जेफ मर्कजे और सीनेटर टॉड यांग द्वारा तिब्बत-चीन संघर्ष के समाधान के लिए प्रस्ताव को बढ़ावा देने के द्विदलीय और द्विसदनीय विधेयक का स्वागत करते हैं। यह तिब्बती लोगों की आशा और दृढ़ संकल्प को पुनर्जीवित करेगा। विधेयक का उद्देश्य तिब्बत की वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति और वर्तमान स्थिति की तात्कालिकता को पहचानते हुए चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान खोजना है। इसी तरह १४ दिसंबर को कनाडा की संसद ने सर्वसम्मति से मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए और तिब्बती प्रतिनिधियों और पीआरसी सरकार के बीच संवाद की बहाली का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उक्त विधेयक और संकल्प निश्चित रूप से चीन-तिब्बत संघर्ष में दोनों पक्षों को विजयी बनाते हुए समाधान के रूप में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को उपयोगी साबित करेगा।

परम पावन दलाई लामा मानवता की एकता की भावना के साथ दूसरों के कल्याण के लिए प्रेम, करुणा और चिंता के विकास पर बल देते हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में उनकी सलाह का पालन कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से युद्ध में उलझी इस दुनिया में शत्रुता को शांत करेगा और प्राकृतिक आपदा, महामारी और अकाल की समस्याओं को दूर करेगा।

परम पावन दलाई लामा न केवल तिब्बत और तिब्बती लोगों के रक्षक और प्रतीक हैं, बल्कि मानवीय मूल्यों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने, तिब्बत की बौद्ध संस्कृति के संरक्षण और प्राचीन भारतीय ज्ञान के पुनरुत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में अद्वितीय नेता हैं। हम परम पावन दलाई लामा को अलगाववादी के रूप में प्रचारित करने के चीनी कम्युनिस्ट सरकार के निराधार आरोपों और दुनिया भर में परम पावन द्वारा दी जर रही मेधावी सेवाओं में बाधा डालने के हर प्रयास का दृढ़ता से विरोध करेंगे। इसके अलावा, अगर चीन परम पावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध और वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को सकारात्मक रूप से पहचानने में विफल रहता है तो पीआरसी सरकार चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने की कुंजी खो देगी।

मैं इस अवसर पर तिब्बती लोगों की ओर से हमें दूसरा घर प्रदान करने के लिए भारत के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ अमेरिका और अन्य सरकारों, तिब्बत पर आठवें विश्व सांसद सम्मेलन के बाद मेक्सिको और स्पेन में नवगठित तिब्बत समर्थक संसदीय समूहों सहित अन्य संसदीय तिब्बत समर्थक समूहों , तिब्बत समर्थन समूहों और सत्य और न्याय का समर्थन करने वाले व्यक्तियों, तिब्बती संघों, स्वैच्छिक तिब्बती समर्थन समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को उनके स्वैच्छिक समर्थन अभियानों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं परम पावन दलाई लामा की लंबी आयु और साथ ही साथ उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। तिब्बत की सच्चाई की जीत हो और दुनिया भर में शांति का वातावरण फैले, इसी कामना के साथ।

कशाग
१० मार्च २०२३

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीचे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com , coordinator@indiatibet.net

March, 2023, Years: 44 Issue: 03 Regd No. : RNI 34636-79

भारत में तिब्बत समर्थक समूहों ने ६४वां तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस मनाया